

# अद्भुत समाचार

हर ख़बर पर पैनी नज़र



वर्ष -09 अंक-121

RNI-No. : UPHIN/2011/43806

लखनऊ, बुधवार, 01 अप्रैल 2020

प्रातः कालीन संस्करण

(हिन्दी दैनिक)

पृष्ठ-8

मूल्य 1 रुपया

## संक्षिप्त समाचार

### उप्र विधानसभा १४ अप्रैल तक बंद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अब १४ अप्रैल तक बंद रहेगी। अधिकारी ने आज इस बात की जानकारी दी। इससे पहले की गई घोषणा में सदन को ३१ मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया था। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि मौजूदा स्थिति और राष्ट्रव्यापी लकडाउन के मद्देनजर बंद को १४ अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

### सहारनपुर मंडल में लॉकडाउन तोड़ने पर ३६४ पर मुकदमा

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के ३६४ लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर मुकदमा कायम किया गया। जबकि ४६ लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला किया गया।

### पाकिस्तान में कोरोना से संक्रमितों की संख्या १८०० के पार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस (कोविड १९) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और आज संक्रमितों की संख्या १८०२ हो गयी और इससे अब तक २६ लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना का पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा प्रकोप नजर आ रहा है। यहां कोरोना से ६५८ लोग संक्रमित हुए हैं जबकि नौ की मौत हुई है। सिंध में ६२७ संक्रमित और आठ की मृत्यु हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना संक्रमित २२१ और छह की मौत की रिपोर्ट है। बलूचिस्तान में १५४ पीड़ित हैं और एक की मृत्यु हुई है। गिलगित-बाल्टिस्तान में १४८ संक्रमित हैं और दो की मौत हो चुकी है।

### दिल्ली मीटिंग से आंध्र लौटे १४ लोग कोरोना पॉजिटिव

अमरावती। आंध्रप्रदेश में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। यहां कल रात को १७ लोगों का पॉजिटिव पाया गया था। अधिकारियों ने आज बताया इनमें से अधिकतर लोगों ने दिल्ली में तबलीगी जमात की बैठक में भाग लिया था। इसके साथ ही राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर ४० हो गई। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार, १७ नए पॉजिटिव मामलों में से १४ या तो दिल्ली में बैठक में शामिल हुए थे या उन लोगों के संपर्क में थे, जो बैठक में शामिल हुए थे। उनमें से लगभग सभी लोग प्रकाशम और गुंटूर जिलों से हैं। अभी इन रोगियों के अधिक विवरण का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही इसे अपडेट किया जाएगा।

## तबलीगी जमात: १०३३ को निकाला, ७०० को किया क्वारंटाइन लॉकडाउन का सेवानिवृत्ति की तारीख पर नहीं पडेगा असर

नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक निजामुद्दीन मरकज से आज तड़के १०३३ लोगों को निकालकर अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर इस मरकज में लगभग १५०० से १७०० लोग ठहरे हुए थे, सभी को इस मरकज से निकाल दिया गया है। ये सभी लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने यहां आए हुए थे। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, मरकज में कुल कितने लोग थे, इसकी पुष्टि जानकारी तो नहीं है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इसमें १५०० से १७०० लोग मौजूद रहे होंगे, जिसमें से ३३४ को अस्पताल भेज दिया गया है और ७०० लोग क्वारंटाइन में हैं। गौरतलब है की तबलीगी जमात का यह भवन छह मंजिला है और इसमें २ हजार लोगों के रहने की व्यवस्था है। यह भवन निजामुद्दीन दरगाह से सटा हुआ है। मरकज में

सोमवार को आए जिस शख्स की मौत हुई थी, अब उसके परिवार को क्वारंटाइन (एकांतवास) में भेजा गया है। इसके साथ ही तेलंगाना और तमिलनाडु में निजामुद्दीन के मरकज से गए लोगों की तलाश जारी है। तेलंगाना में १६४ लोगों को क्वारंटाइन किया गया, जबकि तमिलनाडु में ६८१ लोगों की पहचान करने के साथ



ही उनका टेस्ट किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज में करीब १४ सौ लोग ठहरे हुए थे, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। जमात के विदेशी मेहमानों में ज्यादातर मलेशिया और इंडोनेशिया के नागरिक बताए जा रहे हैं। दिल्ली आने से पहले ये समूह २७ फरवरी से १

मार्च के बीच मलेशिया गया था, जहां ये लोग एक धार्मिक जलसे में शामिल हुए थे। जमात के कई लोगों के कोरोना से पीड़ित होने के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस और मेडिकल की टीम भी सोमवार को फौरन मौके पर पहुंची। सोमवार देर रात तक मरकज को खाली कराने का सिलसिला चलता रहा। मरकज में शामिल १४ सौ लोगों में ११ के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हो चुकी है। इन ११ में १० लोग इंडोनेशिया के नागरिक हैं। ३४ लोगों के सैपल जांच के लिए अस्पताल भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच जान गंवाने वाले शख्स के १८ परिजनों को हैदराबाद में क्वारंटाइन में रखा गया है। मरकज से सोमवार रात भी करीब १०० से ज्यादा संदिग्ध लोगों को तीन बसों में भरकर ले जाया गया। हेल्थ विभाग की टीम, क्षेत्र के डीएम और पुलिस की टीम ने मिलकर इन्हें मरकज से निकाला। इसमें जो ज्यादा

बीमार लग रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि संदिग्ध लोगों को नरेला में आइसोलेशन में भेजा गया है। इस लापरवाही को लेकर तबलीगी जमात के सेंटर के मौलाना के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला किया है। हालांकि, मरकज की तरफ से मौलाना यूसुफ ने सफाई दी है कि लकडाउन लागू होने से पहले ही वहां पर देशी विदेशी गेस्ट ठहरे हुए थे। लिहाजा उन्होंने सरकार के आदेश का पालन किया कि जो जहां है वहीं ठहरे।

### कम्युनिटी किचन सेंटर जोन ५ से भूखे व सभी गरीब परिवारों को रोजाना भोजन करा पाना गम्भीर समस्या है।

अखिलेश दुबे/राकेश पाण्डेय निश्छल लखनऊ। भूखे व गरीबों परिवारों को भोजन ना मिलने की खबर को अद्भुत समाचार ने प्रकाशित किया। खबर छपने के बाद नगर

को संभाल रहे इन अधिकारियों ने रोजाना भोजन देने की बात से पल्ला झाड़ते हुये नजर आये यही के एक अन्य कर्मचारी का कहना है कि यह सब भोजन व्यवस्था नगर निगम के

है कि कैसे सभी भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए जब तक संभव हो पा रहा है हम गरीबों को भोजन कराने व लंच वितरण कराने व पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं प्रयासरत है कि संस्थाओं और लोगों के माध्यम से सहयोग आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा तो आगे भी हम भूखे लोगों को भोजन मुहैया कराने में सक्षम हो पाएंगे ऐसे में सवाल यह उठता है कि अभी तो एक सप्ताह ही बीता है शेष बचे १५ दिनों तक गरीबों व भूखे बेसहारा लोगों को भोजन कैसे मिल पाएगा क्योंकि बिना सरकार के सहयोग के तो भूखे और बेसहारा लोगों को भोजन मिलना नामुमकिन हो जाएगा है ऐसे में सरकार को चाहिए कि क्षेत्र के पार्षदों विधायकों व नेताओं के माध्यम से भी सहयोग करने की अपील करें जिससे कि कोई भी असहाय व गरीब परिवार भोजन के बिना भूखा ना रहे और उसके बच्चे एवं महिलाओं को कम से कम भरपेट भोजन तो मिल सके।



निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मामले को संज्ञानता में लेते हुए लंच पैकेट वितरण कराए गये लेकिन प्रतिदिन भोजन देने की बात चुनौती भरी साबित नजर आ रही है यहां जोन पाँच के जेई व मुख्य अभियंता ए सी सिंह कम्युनिटी किचन सेंटर व्यवस्था

कर्मचारियों व एन जी ओ और अन्य संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं है इन्होंने बताया कि हमारे जोन ५ से ही सरोजिनी नगर क्षेत्र व हज हाऊस में ठहरे लोगों को भी भोजन भिजवाया जा रहा है अब इतना बड़ा क्षेत्र

### २० हजार रेल डिब्बे बनेंगे क्वारंटीन/आइसोलेशन वार्ड

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस 'कोविड-१९' महामारी से निपटने की तैयारियों के तहत ट्रेनों के २० हजार से अधिक कोचों को क्वारंटीन एवं आइसोलेशन वार्डों में बदलने का फैसला किया है जिससे लगभग सवा तीन लाख बिस्तर की क्षमता सृजित होगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में पांच हजार कोचों में बदलाव का काम शुरू भी हो गया है। इनमें ८० हजार बिस्तर उपलब्ध होंगे। रेलवे के पांच जोन पहले ही क्वारंटीन आइसोलेशन कोचों के लिए प्रोटोटाइप्स तैयार



कर चुके हैं। एक कोच में आइसोलेशन के लिए १६ बिस्तर लगाए जाने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं, रेलवे के विभिन्न जोनों के चिकित्सा विभागों और केंद्र सरकार के अधीन आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ

परामर्श में प्रोटोटाइप को मंजूरी मिलने के पश्चात यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार केवल गैर वातानुकूलित आईसीएफ स्लीपर कोचों को ही क्वारंटीन आइसोलेशन कोचों में परिवर्तित किए जाने की योजना है। भारतीय शैली के एक शौचालय को बाथरूम में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें बाल्टी, मग और सोप डिस्पेंसर रखा जाएगा। इसके वाशबेसिन में लिफ्ट टाइप हैंडल वाले नल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी तरह के नल उचित ऊंचाई पर लगाए जाएंगे, ताकि इनसे बाल्टी में पानी भरा जा सके।

## बाहर से लौटे मजदूरों को उप्र में खाद्य एवं रसद विभाग बांटेगा मजदूरों को राशन सैनिटाइज करने पर विवाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाहर से लौटे मजदूरों को सैनिटाइज करने के मसले पर विवाद हो गया। बरेली में लौटे कुछ मजदूरों पर पाइप के जरिए सैनिटाइजर डाले जाने का वीडियो आया, जिसके बाद मजदूरों के साथ

आदेश दिया। उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील करने से पूर्वांचल करने के मसले पर विवाद हो गया। बरेली में लौटे कुछ मजदूरों पर पाइप के जरिए सैनिटाइजर डाले जाने का वीडियो आया, जिसके बाद मजदूरों के साथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग की तरफ से एक अप्रैल (बुधवार) से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों, नरेगा श्रमिकों, श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों तथा नगर विकास विभाग के दिहाड़ी मजदूरों को १ अप्रैल से खाद्य एवं रसद

विभाग की ओर से निरुशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के द्वितीय चरण में १५ अप्रैल से समस्त कार्डधारकों को ५ किलो प्रति यूनिट की दर से निरुशुल्क राशन (चावल) भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत ई-पास से वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण किया

जाना अनिवार्य है। प्रत्येक उचित दर दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन एवं पानी रखा जाए, ताकि हाथ धुलने के उपरांत ही ई-पास का इस्तेमाल हो। राशन की दुकानों पर भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसके लिए प्रत्येक दुकानदार रोस्टर के हिसाब से राशन वितरित करना सुनिश्चित करेगास यदि कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या कलानी को होम क्वारंटाइन

किया गया है तो उस तक होम डिलिवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राशन वितरण के लिए प्रत्येक उचित दर दुकान के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की गई है। उचित दर विक्रेता नोडल अधिकारी तथा ग्राम प्रधान की उपस्थिति में राशन का समुचित वितरण सुनिश्चित कराएंगे।



अमानवीय बरताव का मामला उठा है। जिले के कलेक्टर ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू लकडाउन के छठे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी सीमाएं सील करने का

और चित्रकूट में चार लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार होकर अपने गांव लौटे हैं। इस बीच राज्य के पुलिस प्रमुख हितेश चंद्र अवस्थी ने सोमवार को कहा- बाहर से आने वालों की सेहत की जांच होगी, इसके बाद उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा। उधर, हरदोई जिले में लापरवाही का मामला सामने आया है। वहां एक गांव के बाहर बनाए गए आइसोलेशन से ४० लोग फरार हो गए।

### तबलीगी जमात: उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में हाई अलर्ट

लखनऊ। दिल्ली के निजामुद्दीन में १३ मार्च से १५ मार्च तक लगभग २००० लोगों की धार्मिक बैठक तबलीगी जमात में शामिल हुए लोगों की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के अठारह जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस जमात में हिस्सा लेने वाले तेलंगाना के छह लोगों की मौत हो गई। उन सभी का कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव निकला था। एसपी क्राइम अजय शंकर राय के अनुसार, हाई अलर्ट पर रखे गए इन जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिल्ली में बैठक में भाग लेने वालों की पहचान करने और उनकी मेडिकल जांच करवाने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें मंगलवार शाम तक रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया है। इसके चलते गाजियाबाद, मेरठ,

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बिजनौर, बागपत, वाराणसी, भदोही, मथुरा, आगरा, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों में खासी सतर्कता बरती जा रही है। राज्य सरकार को तबलीगी जमात में भाग लेने वालों की एक सूची मिली है। इस बैठक में भाग लेने वाले लगभग २५० सदस्यों में कोरोनावायरस के प्रारंभिक लक्षण दिखे हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उन लोगों पर नजर रख रहे हैं जो इस जमात में शामिल हुए थे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं कि इसके कारण कोरोना के मामलों में कोई तेजी न आए।"

### लॉकडाउन में श्रमिकों के लिए सड़क पर 'रोटी' की महाभारत

लखनऊ। वैश्विक महामारी का रूप ले चुके कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। इस बीच घरों के लिए केंद्र सरकार ने धार्मिक सीरियल 'रामायण' और 'महाभारत' का पुनरु प्रसारण शुरू कर दिया है। लेकिन महानगरों में रोटी-रोजगार के साधन बंद होने के बाद गांवों की ओर पैदल लौट रहे श्रमिकों के लिए सड़क पर 'रोटी' हासिल करना महाभारत बनता जा रहा है। पिछले पांच दिनों से सड़कों पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जो किसी के भी दिल को दहला प्रयास कर रहे हैं कि इसके कारण कोरोना के मामलों में कोई तेजी न आए।"

मार्च से पूरा देश लॉकडाउन है, लिहाजा महानगरों की सभी सरकारी, गैर सरकारी कंपनियों बंद हो गईं और उनमें मजदूरी करने वाले मजदूर बेकार हो गए। वाहनों में कोई एक हजार तो कोई पांच सौ किलोमीटर का सफर कर पैदल अपने घर लौट रहा है। उन महानगरों से ज्यादा लोग लौट रहे हैं, जहां संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इस बीच सड़कों पर मेला लगा हुआ है और लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। लकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिसकर्मी कहीं लाठी बरसा रहे हैं तो कहीं इंसानों को मेढक जैसे रेंगने के लिए मजबूर कर रहे हैं।



## सम्पादकीय

### बिना निकले जीवन कैसे चले

आंसू, पसीने और खून से लथपथ इंसान आज जिस अग्निपथ पर चल रहे हैं, वह सरकार की नाकामी, गैरजिम्मेदारी से तैयार हुआ है। इस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन अभी वह अपने करतूतों की लीपापोती में जुटी है। जनता को नसीहत दी जा रही है कि सड़क पर न निकले। लेकिन बिना निकले जीवन कैसे चल सकता है, इसकी तैयारी उसने नहीं की। नतीजा ये है कि देश भर में लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर चल रहे हैं, ताकि किसी भी तरह अपने घर पहुंच सकें। जंगलों को काटकर, तालाबों को पाटकर, नदियों पर बांध बनाकर, जो लंबे-चौड़े राष्ट्रीय राजमार्ग गाड़ियों को रफ्तार देने के लिए बनाए गए, वे आज पैदल चलने वालों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। विकास के नाम पर कांक्रिट के जंगल नहीं बनते, तो आज राहगीरों को थोड़ी देर सुस्ताने के लिए पेड़ों की छांव मिल जाती, मिट्टी से भरी पगडंडियां पैरों की थकान थोड़ी कम कर देतीं। लेकिन विनाश और विकास दोनों ही सूरतों में गरीब की जान ही फंसती है। उस पर प्रशासन की संवेदनहीनता उनकी परेशानियां और बढ़ा देती हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दशहत्त के कारण मजदूरों का पलायन कोरोनावायरस की तुलना में एक बड़ी समस्या है। दरअसल लक डाउन की वजह से जिस तरह हजारों मजदूर अपने घरों को लौटने पर मजबूर हुए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार से मंगलवार तक स्टेट्स रिपोर्ट अदालत ने तलब की है। इस बीच केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें मजदूरों की सुध लेने में जुट गई हैं। लेकिन अब तक आवाजाही का सिलसिला थमा नहीं है। बड़ी संख्या में लोग अपने गांव-घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें उन्हें कहीं-कहीं पुलिस-प्रशासन की अमानवीयता का सामना करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश में एक सब-इंस्पेक्टर ने एक महिला मजदूर के माथे पर लिख दिया कि 'मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, मुझसे दूर रहो'। ऐसा लगा कि दीवार फिल्म का शय दोहराया जा रहा है, जिसमें नायक के हाथ पर लिख दिया जाता है— मेरा बाप चोर है। महामारी से बचाने के लिए लोगों को जागरूक और सावधान करने का यह क्रूर तरीका भी किसी महामारी से कम नहीं है। कोरोना का इलाज तो देरसबेर निकल ही जाएगा। लेकिन गरीबों को किसी न किसी बहाने प्रताड़ित करने की यह बीमार मानसिकता शायद लाइलाज ही रह जाएगी। मप्र की इस घटना के बाद अब उत्तरप्रदेश से एक तस्वीर सामने आई है। बरेली जिले में दिल्ली, हरियाणा, नोएडा से आए सैकड़ों मजदूरों, महिलाओं और छोटे बच्चों को जमीन पर बैठाकर उनके ऊपर डिसइंफेक्ट दवाई का छिड़काव किया गया। जिसके बाद बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंखों में जलन की शिकायत की। इस के बावजूद किसी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, बल्कि सबको घर भेज दिया गया। क्या दवा छिड़कने वाले कर्मचारियों को लोहे, कांच, प्लास्टिक के सामान और हाड़-मांस के इंसानों में कोई फर्क नजर नहीं आया। अधिकारसंपन्न ऐसे लोग आखिर खुद किस मिट्टी के बने हैं? बहरहाल यह देखकर थोड़ी राहत मिल रही है कि इस बेहद कठिन समय में भी समाज के बहुत से सामान्य लोग अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए गरीबों की मदद कर रहे हैं। उन्हें जिस तरह भी हो, राहत पहुंचा रहे हैं और बदले में न कोई लाभ चाह रहे हैं, न प्रचार। ऐसे लोगों से ही देश बनता है और बचता भी है। क्योंकि जिस देश में शासक गैरजिम्मेदार हो, वहां जनता पर जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है।

### आर्थिक पैकेज की घोषणा

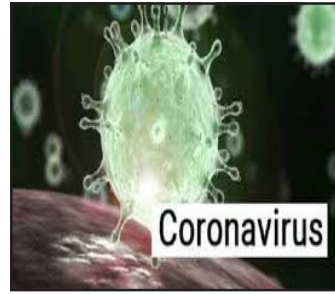
भारत में कोरोना वायरस से फैंली अफरा-तफरी के बीच पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के इस राहत पैकेज का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रखा गया है। सरकार ने दावा किया कि इसका फोकस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर है। मगर बारीक नजर डालें तो इस घोषणा में कई बातें दिखावटी हैं। मसलन, इसमें 39 हजार करोड़ रुपए वो भी हैं, जो निर्माण मजदूर कोष में हैं। सरकार पहले ही राज्य सरकारों को उसका उपयोग करने को कह चुकी है। इसी तरह पीएम किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त वैसे भी किसानों के खाते में जानी थी। उसका कुछ दिन पहले अग्रिम भुगतान कोई अतिरिक्त राहत नहीं है। यही बात मनरेगा मजदूरों में वृद्धि का है, जो मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के साथ पहले से अपेक्षित था। इन सारी रकमों को एक लाख सत्तर हजार में शामिल कर बड़ी राहत का संदेश देना क्या सिर्फ सुर्खियां हासिल करना नहीं माना जाएगा? वैसे ये सच है कि इस पैकेज में घोषित कई उपाय सही दिशा में हैं। जन धन खातों वाली 20 करोड़ महिलाओं को अगले तीन महीने तक 500 रुपए प्रति माह मिलेगा। ये रकम कम है, फिर भी कुछ ना होने से बेहतर है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले लगभग 1 करोड़ परिवारों को अगले तीन महीनों तक गैस के सिलिंडर मुफ्त दिए जाएंगे। यह एलान भी सही दिशा में है। मगर इसके साथ सप्लाई सुचारु बनाने की बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि देश इस समय उधाराव की हालत में है। तमाम तरह की आपूर्तियां बाधित हैं। एक अन्य उपाय के तौर पर दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत आने वाले महिला स्वयंसेवी समूहों की कोलेटरल मुक्त लोन की सीमा को 90 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दिया गया है। इसका लाभ मिलेगा, बशर्त इन समूहों के लिए कामकाज की स्थितियां आम दिनों जैसी हों। गरीब और जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्यान्न मिलते हैं, उसके अतिरिक्त अगले तीन महीनों के लिए पांच किलो गेहूं या चावल मिलेगा। उन्हें इस अवधि में हर महीने एक किलो दाल भी निशुल्क मिलेगी। हालांकि इसमें भी पेच है और आपूर्ति का सवाल है।

# दूसरी बीमारियों का क्या होगा?

सुशांत कुमार

पूरे देश में लागू लॉकडाउन से कोरोना वायरस के संक्रमण पर कितना असर होगा है इसका आकलन अगले कुछ हफ्तों में होगा। भारत में लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ है और पहले छह दिन के आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि यह सफल हो रहा है या नहीं। लकडाउन तीन हफ्ते का है और अगले दो हफ्ते में ही तस्वीर साफ होगी कि संक्रमण को रोकने या इससे लड़ाई में यह उपाय कितना कारगर हुआ। पर यह जरूर तय लग रहा है कि अगर इसी तरह लॉकडाउन चलता रहा तो दूसरी और ज्यादा बड़ी समस्या पैदा हो सकती हैं। एक समस्या तो अर्थव्यवस्था की है। वह पूरी तरह से आईसीयू में चली जाएगी। भारत पहले से आर्थिक मंदी की चपेट में था और अब इस लॉकडाउन के बाद उसकी दशा और बुरी होने वाली है। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, इसे लेकर कई तरह के आकलन हो रहे हैं और आर्थिकों के जानकार अपनी राय दे रहे हैं। पर आर्थिकी से अलग लॉकडाउन का बड़ा असर होना तय है। सरकार और उसके साथ साथ आम लोग भी उम्मीद कर रही है कि पूरे देश को बंद कर देने, लोगों को उनके घरों में रख देने या सामाजिक दूरी बना देने

से कोरोना वायरस का संक्रमण रूक जाएगा या इसके फैलने की स्पीड कम हो जाएगी और इस वजह से दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में जान का नुकसान कम होगा। कुछ हद तक यह मकसद लॉकडाउन से पूरा हो सकता है। हालांकि कुछ ही हद तक क्योंकि लॉकडाउन शुरू होने से पहले कितना संक्रमण फैल चुका है, उसके बारे में किसी



को कुछ पता नहीं है। अगर पहले से संक्रमण फैला हुआ है तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि भारत के पास न तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी हैं और न जरूरी उपकरण हैं। फिर भी अगर मान लें कि इससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल रही है तो बाकी दूसरी बीमारियों का क्या है? भारत में दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों की तादाद भी करोड़ों में है। भारत को दुनिया की डायबिटीज साथ आम लोग भी उम्मीद कर रही है कि पूरे देश को बंद कर देने, लोगों को उनके घरों में रख देने या सामाजिक दूरी बना देने

कैंसर, किडनी रोग, अस्थमा जैसी अनेक बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या करोड़ों में है। कोरोना से लड़ाई में ऐसे मरीजों की अनदेखी हो रही है। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों ने दूसरे मरीजों को भी देखना बंद कर दिया है। दिल्ली में एम्स जैसे अस्पताल ने ओपीडी बंद कर दी है। सोचें, यह क्या बिना सिर-पैर की बात है? कोरोना संक्रमण के



अलावा दूसरी बीमारियों से प्रभावित लोग कहां जाएंगे? निजी अस्पतालों में क्या उन सबका इलाज संभव है? स्वास्थ्य से ही जुड़ा दूसरा संकट यह है कि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में कंपलीट लॉकडाउन से दवा और स्वास्थ्य उपकरण बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट की कमी होने लगी है। अगले एक-दो महीने तो हो सकता है कि दिककत न हो पर अभी उत्पादन और आपूर्ति की चेन टूटी हुई है तो उसका असर तीन महीने बाद दिखेगा। भारत में अनेकों दवाएं बनाने के लिए कंपोनेंट चीन से आता है। वहां से इसका आयात

बंद है। जीवन रक्षक स्वास्थ्य उपकरण बनाने वाली फैक्टरियां भी अभी वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीआई आदि बनाने में लगी हैं। इसका भी असर दूसरी बीमारियों के मरीजों के इलाज पर पड़ेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण का इतना हल्ला मचा है कि डॉक्टर सामान्य मरीजों का भी इलाज करने से बच रहे हैं। चूंकि ज्यादातर सरकारी या निजी अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीआई नहीं हैं। भारत में पीपीआई की क्या स्थिति उसका पता इस तथ्य से लगता है कि कई राज्यों में डॉक्टरों व नर्सों को पीपीआई के नाम पर रेनकोट दिया गया है। इसलिए डॉक्टर मरीजों का इलाज करने से कतरा रहे हैं। उनको खतरा दिख रहा है कि सामान्य सा दिख रहा मरीज कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित न हो। दुनिया जुड़ा दूसरा संकट यह है कि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में कंपलीट लॉकडाउन से दवा और स्वास्थ्य उपकरण बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट की कमी होने लगी है। अगले एक-दो महीने तो हो सकता है कि दिककत न हो पर अभी उत्पादन और आपूर्ति की चेन टूटी हुई है तो उसका असर तीन महीने बाद दिखेगा। भारत में अनेकों दवाएं बनाने के लिए कंपोनेंट चीन से आता है। वहां से इसका आयात

बंद है। जीवन रक्षक स्वास्थ्य उपकरण बनाने वाली फैक्टरियां भी अभी वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीआई आदि बनाने में लगी हैं। इसका भी असर दूसरी बीमारियों के मरीजों के इलाज पर पड़ेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण का इतना हल्ला मचा है कि डॉक्टर सामान्य मरीजों का भी इलाज करने से बच रहे हैं। चूंकि ज्यादातर सरकारी या निजी अस्पतालों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीआई नहीं हैं। भारत में पीपीआई की क्या स्थिति उसका पता इस तथ्य से लगता है कि कई राज्यों में डॉक्टरों व नर्सों को पीपीआई के नाम पर रेनकोट दिया गया है। इसलिए डॉक्टर मरीजों का इलाज करने से कतरा रहे हैं। उनको खतरा दिख रहा है कि सामान्य सा दिख रहा मरीज कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित न हो। दुनिया जुड़ा दूसरा संकट यह है कि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में कंपलीट लॉकडाउन से दवा और स्वास्थ्य उपकरण बनाने के लिए जरूरी कंपोनेंट की कमी होने लगी है। अगले एक-दो महीने तो हो सकता है कि दिककत न हो पर अभी उत्पादन और आपूर्ति की चेन टूटी हुई है तो उसका असर तीन महीने बाद दिखेगा। भारत में अनेकों दवाएं बनाने के लिए कंपोनेंट चीन से आता है। वहां से इसका आयात

## पहले भारत को मयखाने में बदला अब इम्युनिटी बढ़ाने की बात हो रही है

-डॉ. अजय खेमरिया-

केंद्रीय बजट में इस साल नशामुक्ति कार्यक्रम के लिए पहली बार 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भारत में शराब से हर 60 मिनट पर एक नागरिक की मौत हो जाती है। करीब एक लाख मौत तो शराब पीकर गाड़ी चलाते समय निर्दोष राहगीरों और चालकों की हो रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय 96 करोड़ नागरिक नियमित रूप से शराब पी रहे हैं। चरस, अफीम, गांजा, भांग, सिगरेट का नशा करने वाले भारतीयों की संख्या जोड़ दी जाए तो वह करीब 95 करोड़ और होगी। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा तैयार इस शोध में शराब पीने वाले भारतीयों की आयु 90 से 96 वर्षों तक की गई है। 96 करोड़ शराब पीने वालों में से 6.7 करोड़ तो आदतन यानी एडिक्ट हैं। 5.7 करोड़ भारतीय इस वक्त शराब जनित रोगों से ग्रस्त हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री फिट इंडिया अभियान पर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में शराब मार्केट सबसे तेज यानि 11 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2022 में 96.1 बिलियन लीटर शराब की खपत भारत में होगी। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें चुनावी वादों की पूर्ति के लिए अपने ही नागरिकों के जीवन को दांव पर नहीं लगा रही हैं? नजीर के जुटाएंगी। दोनों ही राज्यों में इस प्रावधान को लेकर विरोध हो रहा है। मप्र की सरकार ने तो एक और निर्णय लिया है कि महिलाओं के लिए बड़े शहरों में शराब की अलग से दुकानें खोली जा रही हैं। इन दुकानों पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मिलने वाली ब्रांडेड शराब उपलब्ध होगी। फिलहाल देश में लगभग 2 फीसदी महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। कमलनाथ के इस निर्णय को लेकर भी तीखी आलोचना हुई थी लेकिन शिवराज सिंह ने अभी तक इसे

निरस्त नहीं किया है। इधर केंद्रीय बजट में इस साल नशामुक्ति कार्यक्रम के लिए पहली बार 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भारत में शराब से हर 60 मिनट पर एक नागरिक की मौत हो जाती है। करीब एक लाख मौत तो शराब पीकर गाड़ी चलाते समय निर्दोष राहगीरों और चालकों की हो रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय 96 करोड़ नागरिक नियमित रूप से शराब पी रहे हैं। चरस, अफीम, गांजा, भांग, सिगरेट का नशा करने वाले भारतीयों की संख्या जोड़ दी जाए तो वह करीब 95 करोड़ और होगी। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा तैयार इस शोध में शराब पीने वाले भारतीयों की आयु 90 से 96 वर्षों तक की गई है। 96 करोड़ शराब पीने वालों में से 6.7 करोड़ तो आदतन यानी एडिक्ट हैं। 5.7 करोड़ भारतीय इस वक्त शराब जनित रोगों से ग्रस्त हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री फिट इंडिया अभियान पर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में शराब मार्केट सबसे तेज यानि 11 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2022 में 96.1 बिलियन लीटर शराब की खपत भारत में होगी। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें चुनावी वादों की पूर्ति के लिए अपने ही नागरिकों के जीवन को दांव पर नहीं लगा रही हैं? नजीर के जुटाएंगी। दोनों ही राज्यों में इस प्रावधान को लेकर विरोध हो रहा है। मप्र की सरकार ने तो एक और निर्णय लिया है कि महिलाओं के लिए बड़े शहरों में शराब की अलग से दुकानें खोली जा रही हैं। इन दुकानों पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में मिलने वाली ब्रांडेड शराब उपलब्ध होगी। फिलहाल देश में लगभग 2 फीसदी महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। कमलनाथ के इस निर्णय को लेकर भी तीखी आलोचना हुई थी लेकिन शिवराज सिंह ने अभी तक इसे

में सेवन की जानी वाली शराब में 50 फीसदी हार्ड अल्कोहल होता है जो वैश्विक मानक और प्रचलन के 48 फीसदी की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। यूरोप की तरह शराब का मतलब हमारे यहां वाइन या बीयर भी नहीं है। बल्कि हार्ड ड्रिंक शराब पीते हैं भारतीय जो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जो कैंसर, सिरोसिस सहित करीब 200 तरह की गंभीर बीमारियों की जनक भी है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है

आज 35 फीसदी लोग शराब पी रहे हैं। रांची के पास 600 की आबादी वाले ब्राम्बे गांव को शराब ने विधवा ग्राम में बदल दिया। बेहतर होगा शराब की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिये सामाजिक माहौल भी बनाया जाए। क्योंकि पिछले दो दशकों में युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या इस समय है और शराब की आदी हमारी युवा पूंजी फिट इंडिया

आज 35 फीसदी लोग शराब पी रहे हैं। रांची के पास 600 की आबादी वाले ब्राम्बे गांव को शराब ने विधवा ग्राम में बदल दिया। बेहतर होगा शराब की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिये सामाजिक माहौल भी बनाया जाए। क्योंकि पिछले दो दशकों में युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या इस समय है और शराब की आदी हमारी युवा पूंजी फिट इंडिया



कि एक दशक में भारत में शराब की खपत दोगुनी हो गई है। 2005 में प्रति व्यक्ति यह 2.8 लीटर थी जो 2016 तक 5.7 लीटर हो गई। भारत दुनिया का तीसरा सर्वाधिक शराब सेवन वाला देश है। सरकारी सर्वे के इतर करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो परम्परागत तरीकों से बनी शराब का सेवन कर रहे हैं खासकर वनांचल में ताड़ी, खजूर, गुड़ यहां तक कि मानव मूत्र से बने वाली शराब इसमें शामिल हैं। शराब केवल सरकारी राजस्व तक का मामला नहीं है असल में यह नेताओं, अफसरों और माफिया के गठजोड़ की सम्पन्नता का माध्यम भी है। जितना राजस्व सरकारी खजानों में दिखता है कमोबेश उतना ही इसके खेल में अवैध रूप से भी बनता है। सीएजी की एक हालिया रिपोर्ट में यूपी में मायावती और अखिलेश के कार्यकाल में करीब 25 हजार करोड़ की चपत का खुलासा

आज 35 फीसदी लोग शराब पी रहे हैं। रांची के पास 600 की आबादी वाले ब्राम्बे गांव को शराब ने विधवा ग्राम में बदल दिया। बेहतर होगा शराब की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिये सामाजिक माहौल भी बनाया जाए। क्योंकि पिछले दो दशकों में युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या इस समय है और शराब की आदी हमारी युवा पूंजी फिट इंडिया

आज 35 फीसदी लोग शराब पी रहे हैं। रांची के पास 600 की आबादी वाले ब्राम्बे गांव को शराब ने विधवा ग्राम में बदल दिया। बेहतर होगा शराब की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिये सामाजिक माहौल भी बनाया जाए। क्योंकि पिछले दो दशकों में युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या इस समय है और शराब की आदी हमारी युवा पूंजी फिट इंडिया



# उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 900 के पार पहुंची

**राकेश पाण्डेय निश्चल** लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 900 के पार पहुंच गयी है। राज्य में पांच नये मामले सामने आने के साथ ही मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 909 हो गयी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के पांच नये मामले सामने आये हैं और अब इसके मरीजों की संख्या 909 हो गयी है। प्रसाद ने बताया कि कुल 95 जिलों से ये मामले आये हैं। इनमें भी 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रकरण केवल नोएडा और मेरठ से हैं। उन्होंने बताया " इस समय हम बहुत महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। गत 90 मार्च को देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 900 से कुछ ज्यादा थी। अगले 92 दिनों में वह 900 से एक हजार तक पहुंच गई। 900 की संख्या के बाद का दौर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम लगातार हाथ धोने

और आपसी मेल-मिलाप में दूरी बनाए रखने का पालन करते हुए अगले 98 दिन सतर्कता बरतते हैं तो हमारे यहां मामलों की संख्या बहुत कम रहेगी।" प्रसाद ने कहा कि हम चाहते हैं कि 900 से बाद वाले चरण में उभरने वाले मामले बहुत कम रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि एक-एक जिले में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया जाए, जिनकी निगरानी में अगले एक माह तक कार्यक्रम हो। इस सिलसिले में जो तीन हटस्पट, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात कर दिया गया है जो अगले 95 दिन या एक महीने तक कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये हो रहे काम



की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा " चूंकि नोएडा में कोविड-19 संक्रमण के कई मामले सामने आए। इसलिये मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी नरेन्द्र भूषण को जिम्मेदारी दी है। अब सभी प्राधिकरण, नगर निकाय उनके निर्देशन में काम करेंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरे तालमेल से काम होगा।" प्रसाद ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामले अब तक नहीं आये हैं, वहां जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया है कि वे लगातार निगरानी करें और संदिग्ध मामले का पता चलते ही उसे पृथक सुविधा केंद्र में भेजें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिये आठ लैब काम कर रही हैं। उन्होंने कहा "आज आईसीएमआर के साथ चर्चा हुई जिसमें हमने अनुरोध किया है कि ज़ांसी, प्रयागराज और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में बनी प्रयोगशालाओं को भी अधिकृत किया जाए।

की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा " चूंकि नोएडा में कोविड-19 संक्रमण के कई मामले सामने आए। इसलिये मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के मुख्य अधिशासी अधिकारी नरेन्द्र भूषण को जिम्मेदारी दी है। अब सभी प्राधिकरण, नगर निकाय उनके निर्देशन में काम करेंगे और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पूरे तालमेल से काम होगा।" प्रसाद ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामले अब तक नहीं आये हैं, वहां जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया है कि वे लगातार निगरानी करें और संदिग्ध मामले का पता चलते ही उसे पृथक सुविधा केंद्र में भेजें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिये आठ लैब काम कर रही हैं। उन्होंने कहा "आज आईसीएमआर के साथ चर्चा हुई जिसमें हमने अनुरोध किया है कि ज़ांसी, प्रयागराज और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में बनी प्रयोगशालाओं को भी अधिकृत किया जाए।

## जान गंवाने वालों के परिजन को 25 लाख दे सरकार

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि लॉकडाउन के दौरान काम बंद हो जाने की वजह से घर लौटते हुए जिन लोगों ने रास्ते में जान गंवा दी, उनकी पहचान कर उनके परिवार वालों को 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाए। यादव ने कहा घर लौट रहे जिन लोगों की रास्ते में मृत्यु हो गयी है, सरकार उनकी पहचान कर, उनके पार्थिव शरीर को सम्मान सहित उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करे और 25 लाख रुपये की राशि उनके परिजनों को दे। उन्होंने कहा "सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मेरी अपील है कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने आसपास भटक रहे लोगों की यथासंभव मदद करें।



परिवार वालों को 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाए। यादव ने कहा घर लौट रहे जिन लोगों की रास्ते में मृत्यु हो गयी है, सरकार उनकी पहचान कर, उनके पार्थिव शरीर को सम्मान सहित उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करे और 25 लाख रुपये की राशि उनके परिजनों को दे। उन्होंने कहा "सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मेरी अपील है कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने आसपास भटक रहे लोगों की यथासंभव मदद करें।

## एम्बुलेंस कर्मियों में दिखा असंतोष, सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने का लगाया आरोप

दो माह से वेतन नहीं मिलने की कही बात

बनवारी लाल कुशवाहा शिकोहाबाद। प्रदेश की सबसे सर्वोत्तम जीवन दायिनी सेवा 900, 902 तथा एएलएस, जो पूरे प्रदेश में सभी को स्वस्थ रखने के लिए योगदान दे रही है। परंतु सभी को स्वस्थ रखने वाली इनके राज्य कर्मचारियों का दर्जा लेने व बीमा लेने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लोग 200 से 500 किलोमीटर दूर रहकर यहां सेवा दे रहे हैं। उनके घरों में समस्या पैदा हो रही है, लेकिन मुंह पर लगाने वाला मास्क तक



कर्मचारी बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस का आतंक छाया हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं है, जैसे कि हैंड वश, लिक्विड, फिनायल, क्लोनिंग क्लथ, मास सर्जिकल, कैप, दस्ताने तथा मास्क आदि। वहीं जिलाध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ संजू प्रजापति ने कहा कि 900 व 902 एम्बुलेंस कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्हें 2-3 माह तक की सैलरी तक नहीं दी गई है। इसके अलावा

## शिकोहाबाद के सेक्टर हाउस से बाहर से आए सभी यात्री हुए गायब

बनवारी लाल कुशवाहा शिकोहाबाद। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों के अधिकारियों को बाहरी राज्यों से आए लोगों को 98 दिन के लिए क्वारंटीन करने के



आदेश दिए हैं। जिसके चलते जनपद में पांच स्थानों पर बाहरी व्यक्तियों के लिए स्थान निर्धारित कर अस्थाई सेक्टर हाउस बनाए गए थे। नगर क्षेत्र में बाहरी लोगों को रोकने के लिए नगर के नारायण इंटर कालेज में सेक्टर हाउस बनाया गया जहां पर सोमवार को कई यात्री मौजूद थे लेकिन मंगलवार को जब नारायण इंटर कालेज में जाकर देखा गया तो वहां पर एक

राज्य कर्मचारियों का दर्जा लेने व बीमा लेने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लोग 200 से 500 किलोमीटर दूर रहकर यहां सेवा दे रहे हैं। उनके घरों में समस्या पैदा हो रही है, लेकिन मुंह पर लगाने वाला मास्क तक

नहीं दिया जा रहा है। एंबुलेंसकर्मियों के पास यदि कोई कोरोना का मरीज आ जाए, तो उनके पास सुरक्षा उपकरण ना होने से वह भी इसके ग्रसित हो सकते हैं। इन कर्मचारियों ने कहा कि यदि हमारी मांगों पर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, तो हम ऐसे ही कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने दो दिन पूर्व ही सौतेला व्यवहार कर दिया है। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 2-3 माह तक की सैलरी तक नहीं दी गई है। इसके अलावा

भी यात्री मौजूद नहीं था। सभी यात्री वहां से जा चुके चुके थे। जबकि बाहर से आये लोगों की निगरानी के लिए पुलिस बल के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी तैनात किया गया। लेकिन उसके बाद भी लोग वहां से पलायन कर गए। इस सम्बंध में सीओ इद्रुप्रभा ने बताया कि सभी आसपास के जनपद के रहने वाले लोग थे। लोगो कि संख्या काफी कम थी। वह यहां पर रुकना नहीं चाहते थे।

ऐसे में उन्हें खाना पीने का इंतजाम करा दिया गया। जब वह नहीं रुके तो उन्हें आगे जाने दिया गया। सभी को जनपद की सीमाओं पर छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आए कामगार लोगों की निगरानी गांव राह की जा रही है जो भी बाहर से आ रहा है उसकी सूचना प्रशासन तक पहुंच रही है तथा सभी के स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है।

## लॉकडाउन: भूखे परिवार की मददगार बनी पुलिस

महोबा (उप्र)। कोरोनावायरस का संक्रमण रोकने के लिए 25 मार्च से देश लॉकडाउन है। उत्पीड़न के लिए बदनाम रही पुलिस का अब इसानियत वाला चेहरा भी सामने आ रहा है। कुलपहाड़ के इस्पेक्टर ने मुद्दारी में दो दिन से भूखे एक मजदूर परिवार को सोमवार की शाम राशन सामग्री उपलब्ध कराई। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुद्दारी गांव के राजू रैकवार (48) ने बताया कि वह रोजाना मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। उसने कहा, कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन होने से पिछले छह दिनों से कोई काम नहीं मिला, जिससे बच्चे दो दिन से भूखे थे। उसने बताया कि गांव वालों के कहने पर उसने हिम्मत जुटाकर कोतवाल साहब को फोन कर अपनी दारस्तान सुनाई। लिहाजा सोमवार शाम पुलिस गेहूं, 50 किलोग्राम चावल के अलावा सब्जी और तेल मसाले लेकर उसके घर

पहुंची और उन्हें यह राशन का सामान दिया। इस संबंध में कुलपहाड़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अभिमन्यु सिंह यादव ने कहा कि देश संकट के



दौर से गुजर रहा है। महामारी के साथ-साथ लोगों को भूख से भी बचना है। राजू ने फोन पर राशन न होने की जानकारी दी थी। सो जो बन पड़ा भिजवा दिया है। उन्होंने कहा, हम इसे प्रचारित नहीं करना चाहते क्योंकि पुलिस से पहले हम भी इंसान हैं। पुलिस सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर

## मुख्य चिकित्सा अधिकारी का बेहूदगी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल

अमेठी। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महामारी कोरोना वायरस के चलते पूर्ण रूप से लॉक डाउन किया है देश की जनता पालन भी कर रही है। जहां केंद्र व प्रदेश की सरकार महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 29 दिनों का लक डाउन की घोषणा करते हुये संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये हर

## घरों में श्रद्धा से हुई मां कालरात्रि की पूजा अर्चना

लॉकडाउन को लेकर लोग कर रहे हैं, पूजा अर्चना

बनवारी लाल कुशवाहा शिकोहाबाद। कोरोना को लेकर पूरे जिले में लॉकडाउन लागू होने के बाद लोग अब घरों में ही मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लग गए हैं। तड़के चार बजे से ही घरों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बीच घंटी व आरती की ध्वनि सुनाई देने लगती है। चौत्र नवरात्र के सातवें दिन मंगलवार को मां दुर्गा के स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना हुई। इस बीच लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। एक ओर जहां धर्म के जानकार घरों पर कलश स्थापना कर विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग भी साधारण विधि से पूजा अर्चना के साथ मां की आराधना में जुटे हैं। सुबह-शाम



साथ पूजा में शामिल हो रहे हैं और मां की भक्ति में डूबे हैं। हालांकि मंदिरों में नहीं जाने का भक्तों को आग्रहना में जुटे हैं। सुबह-शाम

मां की सामूहिक आरती आकर्षण बनी है। मां के जयकारे से घर आंगन गुंजायमान हो रहा है। बच्चे, किशोर, नौजवान व बुजुर्ग एक साथ पूजा में शामिल हो रहे हैं और मां की भक्ति में डूबे हैं। हालांकि मंदिरों में नहीं जाने का भक्तों को आग्रहना में जुटे हैं। सुबह-शाम

आयोजित हो रहा है। जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक पूरे उत्साह व श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं।

है, बशर्ते लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें। गौरतलब है कि इसके पूर्व बांदा के डीआईजी दीपक कुमार ने ट्विटर से मिली सूचना पर गुजरत में फंसे एक युवक की बीमार

## मां को हमीरपुर जिले में राशन भिजवाया था। इतना ही नहीं फोन पर मिली सूचना के आधार पर हैदराबाद में फंसे युवक की साढ़े आठ माह की गर्भवती पत्नी काजल (25) को बांदा जिले के रमजपुर गांव से उसकी ससुराल चित्रकूट जिले के सभापुर-तरांग गांव वाहन से भिजवाया गया था।

अधिकारियों की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते साफ दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी सुन सकते हैं मरीज के परिवार व सी०एम०ओ० की दूरभाष पर वार्ता में किस तरह जिले के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार दे रहे हैं पीड़ित को लगभग 32 किमी० पैदल चलकर जांच कराने के निर्देश। आखिर कितना अपने कर्तव्यों का पालन करते सुनाई पड़ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

## जब मार्केट में थैला लेकर निकले डीएम

रियलिटी चीक के दौरान नहीं पहचान सके दुकानदार

किसी भी दुकान पर तय से अधिक रेट पर सामान बिकते हुए नहीं मिला। डीएम ने करीब आधे दर्जन से अधिक दुकानों पर जाकर चेकिंग की थी और रेट भी पूछे लेकिन कहीं कोई अधिक दाम पर सामान बेचना नहीं मिला। हाल ही में डीएम फिरोजाबाद ने खाने पीने के सामान के रेट तय किए हैं। जिसके आधार पर दुकानदारों को सामान ग्राहकों को बेचना है। इस दौरान डीएम ने फिरोजाबाद में करीब एक घंटे तक निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक सेवाओं में आने वाली दुकानों के अतिरिक्त अन्य सामान की खुली हुई दुकानों पर जाने पर उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए बंद कराया। उन्होंने

अनावश्यक रोड पर घूमने वाले लोगों को समझाया कि वह अपने अपने घरों के अंदर ही रहें। निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक के सामान एंजुटे पैण्ट कपड़े की दुकान खुली पाए जाने पर उन्हें फटकार लगाते हुए बंद कराया। इस दौरान उन्होंने सभी दुकानदारों को यह भी समझाया कि वह ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। उन्होंने बाजार में फल व सब्जी की दुकानों से भीड़ लगने की स्थिति को देखते हुये नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर को निर्देश दिये कि वह पुरानी तहसील प्रांगण में फल व सब्जी की दुर.दुर दुकानें लगावें। जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन पूर्णतय: हो सके।

## लाक डाउन पर अमल में आ रही तेजी

नगर के मोहल्ला कुमारन टोला गोला गोकर्णनाथ खीरी। देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ लाक डाउन पर अमल में भी तेजी आती जा रही है ऐसे में खाली इंसान घर बैठे क्या करें बैठे-बैठे बोर हो रहा है ऐसी बोरियत से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं आइए हम आपको बताते हैं यह है गोला

## बरेली में एक ही परिवार के छह सदस्य कोरोना पॉजिटिव

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में नोएडा की सीजफायर फ़ैक्ट्री में काम करने वाले युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके परिवार के पांच और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बरेली शहर के सुभाष नगर क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के घर से एक किलोमीटर दायरे के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पांच किलोमीटर के दायरे में बफर जोन बनाया है। एक किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले सभी घरों में रहने वाले लोगों

की स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग ने शुरू करवा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा विनीत शुक्ला ने बताया कि आज सुबह आई रिपोर्ट के मुताबिक एक ही परिवार के पांच लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले इसी परिवार के एक युवक में कोरोना संक्रमण मिला था। आज केजीएमसी लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक एक 25 वर्षीय युवती दूसरी युवती भी 25 वर्ष तीसरी महिला 50 वर्ष, एक युवक 28 वर्ष और एक 58 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है।

## निशुल्क राशन वितरण आज से राशन वितरण के समय अनिवार्य सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी कराया जाएगा

बनवारी लाल कुशवाहा शिकोहाबाद। शासन द्वारा कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहे अंत्योदय योजना के सभी कार्ड धारकों को एक अप्रैल से निशुल्क राशन वितरण किया जायेगा। इस योजना में शामिल सभी अंत्योदय कार्ड धारक, पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत समस्त मनरेगा जब कार्ड धारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण क्रम के साथ ही नगर क्षेत्र में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं। उपजिलाधिकारी एकता सिंह ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष अन्य पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को पूर्व की भांति नकद मूल्य पर पूरे माह राशन प्राप्त होगा। जिलाधिकारी के आदेश पर उचित दर विक्रेता नोडल अधिकारी की ज्यूटी लगाई गई है। जिनके द्वारा निशुल्क राशन का वितरण अपनी उपस्थिति में कराया जाएगा। राशन वितरण के समय अनिवार्य

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी कराया जाना है। उचित दर विक्रेता द्वारा दुकान पर साबुन एवं पानी की पर्याप्त मात्रा रखी जाये। कार्ड धारकों के हाथ 6 गुलवाने के बाद ही ई.पस मशीन पर बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल का भी सहयोग लिया जा सकता है। उप जिलाधिकारी ने उक्त श्रेणी के सभी कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वितरण के दौरान अपने राशनकार्ड के साथ निशुल्क राशन हेतु मनरेगा जब कार्ड, श्रम विभाग का पंजीयन कार्ड, नगर क्षेत्र का पंजीयन कार्ड लाना अनिवार्य है। पात्र लोग दुकान पर एक साथ एकत्रित न हों। हाथ धुलने के बाद ही मशीन पर अंगूठा निशानी मैच कराये और इस दौरान दुकानदार और नोडल अधिकारी का पूर्ण सहयोग करें।

## स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण

कृष्ण कुमार शुक्ला लखीमपुर-खीरी। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों/जनपदों से वापस आ रहे श्रमिक/मजदूर व कामगारों हेतु निर्मित विभिन्न स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थलों का 31 मार्च को जिलाधिकारी व पुलिस अधि. शिक्षक खीरी द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान कैम्प में पर्याप्त

भोजन, पेयजल, साफ शौचालय, साबुन आदि की व्यवस्था सहित सम्पूर्ण परिसर के साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया। साथ ही यहां रह रहे व्यक्तियों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग मॉटेन करने व चिकित्सा व्यवस्था का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।



## नवयुवको द्वारा भूखे मजदूरो व गरीब परिवारो के बच्चों व महिलाओं को भोजन वितरण कराया गया

अखिलेश दुबे लखनऊ। जोन ५ चित्रगुप्त नगर वार्ड के अंतर्गत आने वाले भोला खेड़ा, इंद्रपुरी में मजदूरों व गरीबों के परिवारों को भूख से तड़पता देख यहाँ भोला खड़ा नहर पर



कुछ नवयुवक समाजसेवियों ने मिलकर अपने अपने द्वारा चंदा लगाकर कुछ रकम एकत्र की और उससे तहरी बनवा कर मोहल्ले व क्षेत्र में रहे हैं गरीब मजदूर व आश्रम हीन परिवारों के बच्चों और महिलाओं को घर घर जाकर तहरी वितरण की यही मोहल्ले

के बीनू यादव अविनाश दुबे, अंकुर पाल, बजरंगी, गोविंद वर्मा, रोहित मोर्य, अंबुजश्रीवास्तव, प्रिंस पाल, शुभम शर्मा, महेश विश्वकर्मा, दीपू यादव, रोहित वर्मा, सुधीर अग्रवाल, सुनील रावत, रामपाल, राहुल घरों जाकर वितरण कराया जिससे कि आपस में भीड़ एकत्र ना हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी भी बनी रहे इन से बातचीत करने पर इन नवयुवको ने बताया कि नगर निगम द्वारा एक दिन यहाँ भोजन वितरण कराया गया लेकिन आज भोजन देने से इंकार कर दिया तब हम सभी ने मिलकर अपने निजी पैसों को इकट्ठा कर गरीब परिवारों को भोजन मुहैया कराने के लिए योजना बनाकर इन गरीब परिवारों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया जिससे कि इन भूखे और गरीब परिवारों के बच्चों व महिलाएं भोजन के अभाव में भूखी ना रहे अखिलेश दुबे ने जब इन से यह इनसे यह ही सवाल किया कि यहां पर कोई नेता विधायक पार्षद अभी तक भोजन वितरण कराने के लिए पहुंचा कि नहीं इन सभी ने बताया कि अभी तक किसी ने आकर हाल भी नहीं पूछा भोजन व राशन वितरण कराना तो बहुत दूर रहा ऐसे में यह भी एक सवाल उठता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में जब देश ने संकट हो तो क्या सत्ता पक्ष के नेता व विपक्ष के नेताओं को समाज में अभावग्रस्त भूखे व गरीब परिवारों के लोगों की मदद करने के लिए आगे आने में इतना डर क्यों जब सरकारी कर्मचारी और संस्थाओं के लोग दिन रात देश व समाज कुमार असहाय लोगों की सेवा के लिए रात दिन लगे हुए हैं तो ऐसे में नेताओं का फर्ज बनता है कि वह समाज में आकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सहयोग करें।

## यूपी में एम्बुलेंस कर्मियों के पास न मास्क न सैनिटाइजर

अद्भुत समाचार नेटवर्क लखनऊ। सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालकों और अन्य सहयोगी कर्मियों ने मास्क, सैनिटाइजर और तनखाह मिलने में हो रही देशी के कारण नाराजगी जाहिर की है। एम्बुलेंस ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा, षट्म रोगियों को ले जा रहे हैं, उनमें से कई कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन हमें मास्क और सैनिटाइजर सहित कोई भी सुरक्षात्मक गियर प्रदान नहीं किया गया है। हम पूरी तरह से घातक बीमारियों के संपर्क में हैं। अस्पताल अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मुड़ी भर, लगभग एक

दार्ज एम्बुलेंस कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर और कीटाणुनाशक प्रदान किए गए थे, जबकि अन्य इनके बिना काम कर रहे हैं। इस बीच, मुख्य चिकित्सा अधिकारी घनश्याम सिंह ने कहा कि केवल पांच एम्बुलेंस कोरोना संदिग्धों को लाने के लिए रखे गए थे, जबकि अन्य सभी एम्बुलेंस सामान्य रोगियों के लिए हैं। उन्होंने कहा, प्लो कर्मचारी कोरोनावायरस रोगियों के लिए चिकित्सा एम्बुलेंस पर तैनात किए गए हैं, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किए गए हैं। केजीएमयू बलरामपुर और सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कहा कि उनका वेतन भी लंबित

है, और कई बार याद दिलाने के बावजूद उन्हें उनका बकाया भुगतान नहीं मिल पाया है। बलरामपुर अस्पताल के एक चालक ने कहा, 'सरकार हमें इन गंभीर समय में काम करने के लिए मजबूर कर रही है। अर्थात् कर्मियों को यह महसूस करना चाहिए कि लॉकडाउन में हमारे परिवारों को भी पैसे की जरूरत होगी।' अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि वेतन और बकाया की मंजूरी के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, 'कई ड्राइवरों को पहले ही वेतन दिया जा चुका है और कुछ ही शेष बचे हैं।'

## पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा बैंक में खाद्यान व अन्य दैनिक उपभोग के उपयोगी सामान का योगदान किया गया

मो० अरशद मऊ। कोरोना वायरस के दृष्टिगत २१ दिवसीय लाक डाउन को लेकर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के द्वारा गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोग भूखे न सोने पायें, के संकल्प के साथ स्थापित किये गये पुलिस पब्लिक अन्नपूर्णा बैंक (आवश्यक वस्तु बैंक) में आज दिनांक ३१.०३.२०२० को सम्भ्रांत व्यक्तियों व पुलिस के माध्यम से भारी मात्रा में खाद्यान व अन्य दैनिक उपभोग के

उपयोगी सामान क्रमशः ३६ कुन्तल ५० किलों आटा/गेहु, ३४ कुन्तल ५५ किलों कुन्तल चावल, १ कुन्तल ४६ किग्रा तेल, ०५ कुन्तल ५७ किलों दाल, ०३ कुन्तल ३६ किलों नमक, ५० किलों चीनी, व अन्य दैनिक उपयोगी सामान संकलित हुआ है जिसमें निम्नलिखित लोगों द्वारा सहयोग दिया गया। थाना मुहम्मदाबाद व पब्लिक के सहयोग द्वारा ५ कुन्तल ४५ किलों चावल, ४ कुन्तल १५ किलों गेहु। टीएसआई मऊ श्री

प्रकाश शुक्ल द्वारा १ कुन्तल चावल, ५० किलों नमक, १० किलों दाल, २० किलों आटा व अन्य सामग्री। श्री राजीव राय द्वारा चावल २५ कुन्तल, आटा २५ कुन्तल, दाल ०५ कुन्तल १० किलों, नमक २ कुन्तल ५० किलों, तेल १ कुन्तल, मसाला १२०० पीस। श्री वेद मिश्र द्वारा आटा १०० किलों। मुथुत फायनेंस द्वारा आटा ३ कुन्तल, चावल १ कुन्तल ७५ किलों, दाल ३० किलों, तेल ३६ किलों चीनी ५० किलों, नमक

## तब्लीगी जमात में शिरकत करने वाले लोगों को तेजी से तलाश की जाए : योगी

अद्भुत समाचार नेटवर्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तब्लीगी जमात में शिरकत करने वाले लोगों को तेजी से तलाश की जाए, और वे जहां भी मिले उन्हें तत्काल क्वारंटीन किया जाए। योगी आदित्यनाथ सोमवार को आगरा और मेरठ का दौरा रद्द कर लखनऊ पहुंचे और अधिकारियों से प्रदेश भर में तब्लीगी जमात में शिरकत करने वाले लोगों की तलाश करने के साथ ही इन सभी को क्वारंटीन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि षूरे प्रदेश में लकडाउन का पूरी तरह पालन हो, इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी की जमात से जुड़े हुए लोगों की तेजी से तलाश की

## यूपी के इंजीनियर्स मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे पांच करोड़

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अभियंत्रण विभाग और निगम में कार्यरत लगभग १५००० अभियंता अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेगा। यह धनराशि लगभग पांच करोड़ रुपये होगी। यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष यादव ने बताया कि एक दिन के वेतन के अलावा एसोसिएशन ने सभी अभियंताओं के सहयोग से ११ लाख रुपये की सहायता ६ नगराशि अलग से देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदानमंत्री के लॉकडाउन को शतप्रतिशत सफल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी परिस्थिति में अभियंता संवर्ग कई स्तर पर सहयोग कर रहा है। कुछ इंजीनियर स्वतः ही किसी ना किसी राहत कोष में सहायता कर रहे हैं। अभियंता विद्युत, जल एव अन्य आवश्यक सेवाओं की पूर्ति करने में अथक प्रयास कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में कालाबाजारी, जमाखोरी पर लगाम लगाने से लेकर कंट्रोल रूम में कार्यरत है। एसोसिएशन प्रदेश सरकार को इस बॉत का पूरा विश्वास दिलाता है कि इस आपदा की घड़ी में अभियंता संवर्ग की जैसी जरूरत होगी अभियंता संवर्ग सरकार के निर्देश का पालन करेगा।



आर्मी मेडिकल अफसरों के साथ ही पूर्व स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सेवा लें। योगी ने कहा कि सरकार के पास उन लोगों का पूरा आंकड़ा मौजूद है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की सीमाओं से प्रदेश के अंदर अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया है। इन सभी लोगों को हर हाल में चिन्हित कर लिया जाए। इनको हर हाल

में क्वारंटीन रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों में मौजूद उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पूरी मदद की जाए, उनके भोजन और आश्रय आदि का प्रबंध अवश्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्संस्थानों के मालिक अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के भोजन का हर हाल में प्रबंध करें, यदि वे नहीं कर पा रहे हैं तो प्रशासन को सूचित करके सभी श्रमिकों और कर्मचारियों के भोजन का इंतजाम सुनिश्चित कराए, प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। राशन वितरण प्रणाली और बैंकों से लेन देन के दौरान भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए, पुलिस और होम गार्ड के जवानों की मदद से सारे हेल्थ प्रोटोकल पूरे कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम सामाजिक संस्थाएं और लोग इस आपदा

के वक्त में लोगों के भोजन आदि की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से समन्वय स्थापित करके कुछ आश्रय स्थलों पर इनके माधुयम से भी भोजन पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि आटा मिलें, दाल मिलें, तेल मिलें सभी हेल्थ प्रोटोकल का पालन करते हुए चलवाए जाएं। योगी ने खासतौर पर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि किसी भी जनपद में सामानों की ओवर चार्जिंग नहीं होने दी जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुछ जिलों में अधिकारियों ने स्वयं बाजारों में उतरकर जमाखोरी कालाबाजारी करने वालों और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसी प्रकार सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करें।

## दिल्ली के निजामुद्दीन मे तब्लीगी मरकज में शामिल रहे लोगों की तलाश शुरू

लखनऊ। दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के मरकज ने देश भर में हड़कंप मचा गया है। लॉकडाउन के बीच इस हुए इस मरकज में देश और दुनिया से करीब १५०० लोग शामिल हुए। जिनमें अब कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। मरकज में शिरकत करने वाले ६ लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दिल्ली में सैकड़ों संक्रमित लोगों को अस्पतालों में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं इस तब्लीगी मरकज में शामिल रहे सैकड़ों लोगों की तलाश भी शुरू हो गयी है। मंगलवार को सूचना मिली कि जमात के कुछ लोग लखनऊ के

कैसरबाग में एक मरकज में मस्जिद में ठहरे हुए हैं। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने मौके पर पहुंच कर इन लोगों से पूछताछ की। यहां करीब आधा दर्जन विदेशी नागरिक मिले हैं। इनमें किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने सभी विदेशी नागरिकों का मेडिकल चेकअप कराकर क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। यह सभी यहां पिछले १३ मार्च से रुके हैं। पता चला कि ये विदेशी नागरिक एक धार्मिक जलसे में भाग लेने आए

थे। खुफिया और एलआईयू की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मस्जिद पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर अमीनाबाद, मंडियांव और काकोरी इलाके की मस्जिदों में भी कई विदेशी नागरिकों के रुके होने की खबर है। मंडियांव में १७ बांग्लादेशी नागरिकों के रुके होने की सूचना मिली है। बता दें कि सरकार के पास सूचना है कि दिल्ली में हुई तब्लीगी मरकज में यूपी के करीब २० लोग शामिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये २० लोग अभी तक लखनऊ नहीं लौटे हैं, ये अभी नई दिल्ली में ही हैं।

## गरीबो एवं असहाय परिवारों की सहायता हेतु ५ लाख रुपए की महापौर को सौंपी धनराशि

अखिलेश दुबे लखनऊ। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और महापौर के कुशल नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम द्वारा कोरोना के इस महाप्रकोप की विपत्तिकाल के समय गरीबों,बेघरों एवं असहाय लोगों के लिए एवं लखनऊ में कोई भूखा न सोए मुहीम के तत्वाधान में महापौर के प्रयासों से सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलजी ने नगर निगम के प्रकल्प अन्नदाता को ५ लाख रुपये की सहयोग राशि पत्र महापौर के आवास पर पहुंच कर सौंपते हुए आर.टी.जी.एस के माध्यम से ५ लाख रुपये की

सहयोग राशि अन्नदा ग्रेन बैंक नगर निगम लखनऊ के खाते में ट्रांसफर की इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने उनके द्वारा किये गए इस अनुपम प्रयास की सराहना करते हुए धन्यवाद भी दिया गौरतलब है कि महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया द्वारा गरीबों एवं असहाय की सहायता के लिए सभी सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं से अपने स्तर से मदद करने के लिए आह्वान किया था उसी क्रम में सिपेट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉ० संदेश कुमार जैन ने महापौर से वार्ता कर मदद करने की इच्छा

जताई थी जिस हेतु डॉ० जैन के प्रतिनिधि के रूप में डॉ० यूपी० नितेश जैन जी (प्रशासनिक अधिकारी-सिपेट) एवं जसराम सिंह जी (तकनीकी विशेषज्ञ) ने महापौर को ५ लाख की सहयोग राशि प्रदान किया इस दौरान महापौर संयुक्ता भाटिया को उनके आवास पर पहुंचकर राशि पत्र सौंपते समय सीपेट संस्था के मुख्य प्रबंधक डॉ० यूपी सिंह, प्रशासनिक अधिकारी नितीश जैन, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी जसराम सिंह जी भी उपस्थित रहे।

## ९५ लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा बनाने के उपकरण के साथ एक गिरफ्तार

मो० अरशद मऊ। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान दाउदपुर के पास से हरेन्द्र यादव पुत्र बासुदेव यादव निवासी दाउदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से ६५ लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, २ किलों ५०० ग्राम यूरिया, १ किलों ५०० ग्राम

नौसादर, ५०० ग्राम फिटकरी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० १६९/२० धारा ७२२,२७३ भादवि० तथा ६० आबकारी धनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

## ६७० लोगों को लंच पैकेट वितरित किया गया

मो० अरशद मऊ। कोरोना वायरस के दृष्टिगत २१ दिवसीय लाकडाउन के सातवें दिन आज दिनांक ३.०३.२०२० को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा पूरे जनपद में गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को भोजन राशन उपलब्ध कराये जाने के क्रम में-६७० लोगों को लंच पैकेट वितरित किया गया, ७४८

परिवारों में खाद्य सामग्रीश्राशन क्रमशः १५ कुन्तल ७७ किग्रा आटा, १४ कुन्तल ६५ किलों चावल, ०७ कुन्तल ८६ किग्रा आलू, ०२ कुन्तल २० किग्रा प्याज, ०२ कुन्तल ७० किग्रा दाल, ६८ किग्रा तेल, १ कुन्तल ०५ किग्रा चीनी, ०१ कुन्तल २० किग्रा नमक व अन्य सामान (चायपत्ती, साबुन, बिस्किट, मसाला, दवा, मंजन मास्क) इत्यादि वितरित किया गया।



## आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया गया

मो० अरशद मऊ। कोरोना वायरस के दृष्टिगत २१ दिवसीय लाकडाउन को लेकर जिलाधिकारी मऊ श्री ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा जनपद में कमशः कोपागंज, कुर्थाजाफरपुर, ढाढाचवर, कोईरियापार, भातकोल, कैलेण्डर, कोईरियापार, भातकोल, कैलेण्डर, चिरैयाकोट, सरसेना, वनदेवी, पिपरीडीह, बढुआगोदाम,



सरायलखंसी, गाजीपुर तिराहा व भीटी आदि स्थानों पर भ्रमण कर जायजा लिया गया तथा ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय में व्यवस्थापित आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तथा सर्व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



# केन्द्र पलायन रोके और सही जानकारी देने के लिये २४ घंटे के भीतर पोर्टल बनायेरु सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के कोरोनावायरस की वजह से कामगारों के पलायन को रोकने और २४ घंटे के भीतर इस महामारी से जुड़ी जानकारीयां उपलब्ध कराने के लिये एक पोर्टल बनाने का केन्द्र को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस पोर्टल से महामारी से संबंधित सही जानकारी जनता को उपलब्ध करायी जाये। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केन्द्र को यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "यह दशहता वायरस से कहीं ज्यादा जिंदगियां बर्बाद कर देगा।" साथ ही पीठ ने केन्द्र से कहा कि देश के तमाम आश्रय गृहों में पनाह लिये इन

कामगारों का चित्त शांत करने के लिये प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सभी आस्थाओं के समुदायों के नेताओं की मदद ले। पीठ ने कहा कि इन आश्रय गृहों का संचालन पुलिस को नहीं बल्कि स्वयंसेवकों को करना चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह पलायन कर रहे इन कामगारों को रोके और उनके भोजन, रहने और चिकित्सा सुविधा आदि का बंदोबस्त करे। केन्द्र ने इन कामगारों को सैनिटाइज करने के लिये उन पर रसायन युक्त पानी का छिड़काव करने के एक याचिकाकर्ता के सुझाव पर कहा कि यह वैज्ञानिक तरीके से काम नहीं करता है और यह उचित तरीका नहीं है। इस बीच, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों को

इन कामगारों के मसले पर विचार करने से रोकने से इंकार कर दिया और कहा कि वे अधिक बारीकी से इस मामले की निगरानी कर सकते हैं। हालांकि, न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह शीर्ष अदालत के आदेशों के बारे में उच्च न्यायालयों को अवगत कराने के लिये सरकारी वकीलों को निर्देश दे। पीठ ने केन्द्र से कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी के मुद्दे के संदर्भ में केरल के कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन और पश्चिम बंगाल के एक सांसद की पत्र याचिकाओं पर विचार करे। न्यायालय ने इन याचिकाओं की सुनवाई सात अप्रैल के लिये स्थगित करते हुये केन्द्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कामगारों के आश्रय स्थलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी



स्वयंसेवियों को सौंपी जाये और इनके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाये। केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस समय

जनरल ने कहा कि इस महामारी से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिये समूचे देश को लकडाउन करने की आवश्यकता हो गयी है ताकि लोग दूसरों के साथ घुले मिलें नहीं और सामाजिक दूरी बनाने के सूत्र का पालन करते हुये एक दूसरे से मिल नहीं सकें। मेहता ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कामगारों का पलायन नहीं हो। ऐसा करना उनके लिये और गांव की आबादी के लिये भी जोखिम भरा होगा। जहां तक ग्रामीण भारत का सवाल है तो यह अभी तक कोरोनावायरस के प्रकोप से बचा हुआ है लेकिन शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे १० में से तीन व्यक्तियों के साथ यह वायरस जाने की संभावना है।" उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय पलायन

पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बारे में राज्यों को आवश्यक परामर्श जारी किये गये हैं और केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के अनुसार करीब ६,६३,००० व्यक्तियों को अभी तक आश्रय प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि २२,८८,००० से ज्यादा व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है क्योंकि सभी जरूरतमंद, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे कामगार और दिहाड़ी मजदूर हैं जो कहीं न कहीं पहुंच गये हैं और उन्हें रोककर आश्रय गृहों में ठहराया गया है। पीठ ने शुरू में टिप्पणी की, "हम २४ घंटे के भीतर सूचनायें उपलब्ध कराने के लिये पोर्टल के बारे में आदेश पारित करेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों को आपने रोका है उनकी सही तरीके से देखभाल हो और

उन्हें भोजन, रहने की जगह, पौष्टिक आहार और चिकित्सा सुविधा मिले। आप उन मामलों को भी देखेंगे जिनकी पहचान आपने कोविड-१९ मामलों और अलग रहने के लिये की है। मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार जल्द एक ऐसी व्यवस्था लागू करेगी जिसमें कामगारों के व्याप्त भय पर ध्यान दिया जायेगा और उनकी काउन्सलिंग भी की जायेगी। पीठ ने मेहता से सवाल किया, "आप कब ये केन्द्र स्थापित कर देंगे? परामर्शदाता कहां से आ रहे हैं? उन्हें आप कहां भेजेंगे?" इस पर मेहता ने कहा कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से इन प्रशिक्षित काउन्सलर को भेजा जायेगा, इस पर पीठ ने कहा, "देश में ६२० जिले हैं। आपके पास कुल कितने काउन्सलर हैं? हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह दशहता वायरस से कहीं ज्यादा जिंदगियां बर्बाद करदेगा।"

## पीएम केयर्स फंड में योगदान देने वालों का मोदी ने जताया आभार, कहा- सामूहिक ताकत दिलायेगी जीत

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिये गठित किए गए 'आपात स्थिति प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)' में योगदान के लिये उद्योगपतियों, खिलाड़ियों, फिल्मी कलाकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, मीडियाकर्तियों और आम लोगों का आभार प्रकट करते हुए मंगलवार को कहा कि कोरोना से युद्ध में देश की यही सामूहिक ताकत जीत दिलायेगी। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, "पीएम केयर्स फंड में समाज के हर वर्ग के लोगों ने योगदान दिया है। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा कोविड-१९ के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने के लिये दिया है।" उन्होंने कहा, "कोरोना से लड़ने के लिए हर क्षेत्र के लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। देश की यही सामूहिक ताकत है, जो इस लड़ाई में जीत दिलाएगी।" कोष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के योगदान की सराहना करते

हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र की कंपनियों ने केवल भारत के विकास की गति को आगे बढ़ा रही हैं बल्कि

कोविड-१९ के संकट के समय देश का अरुध स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये भी योगदान कर रही हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को दो दिनों का वेतन देने के लिए विशेष धन्यवाद। मोदी ने कोष में पीएम-केयर्स में योगदान के लिये उद्योगपति मुकेश एवं नीता अंबानी तथा सुनील भारती मित्तल को धन्यवाद दिया और कहा कि इस मानवीय प्रयासों में इन समूहों के योगदान से काफी भारतीयों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सिने अभिनेता राष्ट्र

के बेहतर स्वास्थ्य के लिये योगदान दे रहे हैं। वे जागरूकता फैलाने में भी शामिल रहे हैं, साथ ही पीएम-केयर्स में भी योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में नाना पाटेकर, अजय देवगन, आर्यन कार्तिक, शिल्पा शेटी, बादशाह, रणवीर शौरी आदि को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे कोरोना वायरस को परास्त करने में शोध कार्य को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कोरोना से लड़ाई में खिलाड़ियों के योगदान का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, "मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे कठिन परिश्रम करने वाले खिलाड़ी कोविड-१९ के खिलाफ लड़ाई में आगे हैं।" उन्होंने पीएम-केयर्स में योगदान के लिये रजत शर्मा, प्रभु चावला का आभार जताया। मोदी ने कहा कि जब भी देश सेवा की बात सामने आती है, तब योगगुरु रामदेव जी हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में इस योगदान के लिए आपका बहुत-बहुत आभार।



## प्रधानमंत्री मोदी की मां ने कोविड-१९ कोष में २५ हजार रुपये दान किये

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां हीराबेन ने अपनी बचत में से देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिये बनाए गए विशेष कोष में मंगलवार को २५ हजार रुपये दान किये। प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी ने कहा कि हीराबेन ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाए

गए पीएम-केयर्स कोष में पैसे जमा किये। पंकज मोदी ने कहा, इससे पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत अभियानों के लिये ५ हजार रुपये दान किये थे। अब उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिये बरसों से बचाकर रखे गए २५ हजार रुपये दान किये हैं। हीराबेन मोदी पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के निकट रायसण गांव में रहती हैं।

ममता बनर्जी ने कोविड-१९ से लड़ाई में निजी बचत से १० लाख रुपये दान किए

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-१९ से लड़ाई में सहयोग हेतु मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राज्य आपातकालीन राहत कोष में पांच-पांच लाख रुपये दान किया। बनर्जी ने ट्विटर पर कहा कि यह योगदान उनकी व्यक्तिगत बचत से किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं एक विधायक या मुख्यमंत्री के रूप में कोई वेतन नहीं लेती हूँ और सात बार सांसद होने के बावजूद मैंने अपनी सांसद पेंशन को छोड़ दिया है। मैं सीमित साधनों में जीती हूँ। मेरी आय का प्राथमिक स्रोत मेरे संगीत और पुस्तकों से मिलने वाली रयल्टी है।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "मेरे सीमित संसाधनों में

हमारे देश के प्रयासों का समर्थन किया जा सके।" पश्चिम बंगाल में अब तक कोविड-१९ के २७मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें से तीन व्यक्तियों ने गंभीर सांस की बीमारी के कारण दम तोड़ दिया।

## बाहर से आ रहे लोग बन रहे चुनौती

मोहम्मदी-खीरी। लाकडाउन में बाहर से आ रहे लोग प्रशासन के लिये ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिये चुनौती बने हुए हैं। भूखे-प्यासे रोज आ रहे लोगों को भोजन करा रही मां जानकी रसोई के सहयोग के लिये आज पुलिस भी कन्धे से कन्धा मिलाकर उत्तर आयी और परेशान हाल लोगों को भोजन पहुंचाने से लेकर पैदल यात्रियों स्वयं, भोजन परोसने तक का काम आज सीओ, कोतवाल, दरोगाओं, सिपाहियों ने कर मानवता की मिसाल पेश की। रोडवेज परिसर के निकट समाजसेवी शिवम राठौर एवं उनके सहयोगियों के द्वारा असहाय एवं दीन हीन लोगों के भोजन के पैकेट बांटने शुरू करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि भोजन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना नहीं है, लेकिन अधिक वितरण बिन्दु भौतिक दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मदद की कोशिश कर रहे उद्योगपतियों को मेडिकल स्टॉफ के लिए रक्षात्मक उपकरण, जांच किट और वेंटिलेटर दान करने में मदद करनी चाहिए जिनकी इस समय सर्वाधिक आवश्यकता है।

से मैं प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में पांच लाख रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य आपातकालीन राहत कोष में पांच लाख रुपये का योगदान दे रही हूँ, ताकि कोविड-१९ से लड़ने में



हमारे देश के प्रयासों का समर्थन किया जा सके।" पश्चिम बंगाल में अब तक कोविड-१९ के २७मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें से तीन व्यक्तियों ने गंभीर सांस की बीमारी के कारण दम तोड़ दिया।

## कोरोना के संकट से निपटने में विश्व के लिये भारत उम्मीद की किरण: वेंकैया नायडू

नयी दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये घोषित देशव्यापी पूर्ण बंदी (लॉकडाउन) के पहले सप्ताह में केंद्र, राज्य सरकारों तथा देश के नागरिकों द्वारा किए गए संकल्पबद्ध प्रयासों की सराहना करते हुये कहा है कि इस संकट से निपटने में विश्व के लिये भारत उम्मीद की किरण है। नायडू ने मंगलवार को लॉकडाउन का पहला सप्ताह पूरा होने पर जारी अपने बयान में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित रखने के लिए लकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों तथा देश के नागरिकों द्वारा किए गए संकल्पबद्ध प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा, "संक्रमण के विरुद्ध वैश्विक अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है कि भारत इस संक्रमण को सीमित रखने में सफल हो। मुझे आशा है कि विपत्ति की इस घड़ी में, भारत ही विश्व को आशा का प्रकाश दिखाएगा।" उल्लेखनीय है कि शुरु करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सप्ताह मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके तहत पूर्ण

बंदी के दौरान नागरिकों को अनिवार्य सेवाओं एवं वस्तुओं की ही आपूर्ति की जा रही है। नायडू ने संकट की इस घड़ी में देशवासियों से हरसंभव सहायता करने की अपील करते हुये सरकार के राहत कोष में दान



देने का भी आह्वान किया। उन्होंने लॉकडाउन का आगे भी नियमित तौर पर पालन करने की अपील करते हुये कहा, "जरूरी है कि हर नागरिक यथासंभव सहयोग करे, सामाजिक और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखे तथा स्वच्छता नियमों का पालन करे।" इस दौरान उपराष्ट्रपति ने चिकित्साकर्मियों के सेवाभाव को भी सराहनीय बताया। उन्होंने कहा, "आपदा के इस समय, प्रथम पंक्ति में योद्धा की तरह खड़े कोरोना के खिलाफ अभियान शुरु करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सप्ताह मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके तहत पूर्ण

## राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंजीनियरिंग की JEE&Main परीक्षा स्थगित की, मई में हो सकती है आयोजित

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे के चलते आईआईटी एवं एनआईटी में प्रवेश के लिए अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य २०२० को स्थगित कर दिया गया है और अब इसे मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मुख्य २०२० परीक्षा स्थगित करने की

घोषणा की थी जो ५, ७, ९, ११ अप्रैल २०२० को आयोजित होनी थी। एनटीए ने अधिसूचित किया है कि अब यह परीक्षा मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में स्थिति की समीक्षा करने के बाद तिथि की घोषणा की जायेगी। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उम्मीद व्यक्त की है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी लेकिन अभी के में एनटीए स्थिति की

करीबी समीक्षा कर रही है। इसी के अनुरूप तब की स्थिति को देखते हुए १५ अप्रैल के बाद परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। मंत्रालय के अनुसार, एनटीए छात्रों को ताजा स्थिति से अवगत कराता रहेगा और उन्हें बदलाव एवं परीक्षा तिथियों के बारे में भी अग्रिम जानकारी देता रहेगा। गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिये २१ दिनों के देशव्यापी लकडाउन की घोषणा की है।

## केजरीवाल ने कहा- निजामुद्दीन मरकज से १,५०० लोग निकाले गए, आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि यहां निजामुद्दीन मरकज से १,५०८ लोगों को निकाला गया है जिनमें से ४४१ को कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निजामुद्दीन (पश्चिम) में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए १,१०७ लोगों को पृथक रखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के ६७ मामलों में से २४ लोग वे हैं जो इस महीने के शुरू में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। केजरीवाल ने कार्यक्रम के आयोजकों की निन्दा की और कहा कि इन लोगों ने महामारी के चलते दूसरे देशों में हजारों लोगों की मौत को देखते हुए ऐसे समय में इस तरह का

धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर बहुत ही "गैर जिम्मेदाराना" काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आयोजकों के नामों को पृथक रखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगभग ३,७७५ स्कूलों और रैन बसेरों से बुधवार से लगभग १०-१२ लाख लोगों को भोजन के पैकेट बांटने शुरू करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि भोजन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना नहीं है, लेकिन अधिक वितरण बिन्दु भौतिक दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मदद की कोशिश कर रहे उद्योगपतियों को मेडिकल स्टॉफ के लिए रक्षात्मक उपकरण, जांच किट और वेंटिलेटर दान करने में मदद करनी चाहिए जिनकी इस समय सर्वाधिक आवश्यकता है।



मामलों में से ८६ रोगियों की हालत स्थिर है। दो लोगों को अक्सीजन दी जा रही है और एक अन्य को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लगभग ३,७७५ स्कूलों और रैन बसेरों से बुधवार से लगभग १०-१२ लाख लोगों को भोजन के पैकेट बांटने शुरू करेगी। केजरीवाल ने कहा कि हालांकि भोजन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना नहीं है, लेकिन अधिक वितरण बिन्दु भौतिक दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मदद की कोशिश कर रहे उद्योगपतियों को मेडिकल स्टॉफ के लिए रक्षात्मक उपकरण, जांच किट और वेंटिलेटर दान करने में मदद करनी चाहिए जिनकी इस समय सर्वाधिक आवश्यकता है।

## सरकार ने विदेशी तबलीगी कार्यकर्ताओं को पर्यटन वीजा जारी करने पर लगाया प्रतिबंध

नयी दिल्ली। सरकार ने भारत की यात्रा करने और तबलीगी गतिविधियों में हिस्सा लेने की गृह मंत्रालय को पर्यटन वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह फैसला ये सामने आने के बाद लिया गया है कि एक जनवरी से अब तक लगभग २,१०० विदेशी भारत में

आए और देश के विभिन्न हिस्सों में तबलीगी गतिविधियों में लग गए। इनमें से कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गये हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्रालय को सलाह दी गई है कि दूसरे देशों में भारतीय मिशनो से अनुरोध किया जा सकता है कि वे ऐसे विदेशी को पर्यटक वीजा देने से परहेज करें, जो तबलीगी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से कहा कि उसे ऐसे आवेदकों को पर्यटक वीजा देने से पहले उनके भारत में उतरने, वापसी के टिकट और खर्चों के संबंध में जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिये।

## खाद्यान्न का रोस्टर जारी

कृष्ण कुमार शुक्ला लखीमपुर-खीरी। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिनके पास राशन कार्ड हैं और जिनके राशन कार्ड ई-पास मशीन में दर्ज हैं उन्हें खाद्यान्न दिया जाएगा साथ ही इन राशन कार्ड धारकों में से समस्त अंतोदय कार्ड धारक, पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों में सम्मिलित मन्तरंगा कार्ड धारक, श्रम विभाग के निर्माण श्रमिक, नगर विकास विभाग में पंजीत दिहाड़ी मजदूरों को निशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को २० किलो गेहूँ तथा १५ किलो चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को ५ किलो

खाद्यान्न प्रति यूनिट दिया जाएगा। दिनांक १ अप्रैल से ३ अप्रैल तक अंतोदय कार्ड धारकों को ४ अप्रैल से ७ अप्रैल तक पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को ८ अप्रैल से २५ अप्रैल तक अवशेष सभी श्रेणियों के लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण नियम अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। वितरण दिवस में यदि कोई लाभार्थी जिसे उस रोस्टर की जानकारी ना हो पाने के कारण दुकान पर आता है निराश्रित, विधवा, दिव्यांग यदि उचित दूकान पर किसी भी स्थिति में आते हैं तो उन्हें राशन दिया जाएगा।





# शेयर बाजार में तेजी लौटी

मुंबई। विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार ने आज साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के साथ वित्त वर्ष 2019-20 को अलविदा कहा। बीएसई का संसेक्स आज 9,027.90 अंक यानी 3.62 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,862.86 अंक पर बंद हुआ। कोरोना वायरस 'कोविड-19' का संक्रमण दुनिया भर में फैलने से पिछले दो महीने से जारी दबाव के कारण पूरे वित्त वर्ष के दौरान इसमें 6,208.82 अंक (23.20 प्रतिशत) की गिरावट रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 3,946.65 अंक यानी 3.22 फीसदी की बढ़त में 1,56,09.05 अंक पर रहा और इस प्रकार पूरे वित्त वर्ष के दौरान यह 3026.95 अंक (26.03 प्रतिशत) लुढ़क गया। मझौली और छोटी कंपनियों में अपेक्षात कम तेजी रही। बीएसई का मिडकैप 2,846.83 प्रतिशत की तेजी के साथ 90,566.63 अंक पर और स्मलकैप 2.62 प्रतिशत की बढ़त में 6,602.62 अंक पर



बंद हुआ। इसके बावजूद वित्त वर्ष के दौरान मिडकैप 8,605.66 अंक (39.09 प्रतिशत) और स्मलकैप 4,892.84 अंक (36.06 प्रतिशत) की गिरावट में रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से विदेशी शेयर बाजारों के साथ ही घरेलू स्तर पर भी मजबूती दर्ज की गयी। बीएसई के तेल एवं गैस समूह में पौने नौ फीसदी और ऊर्जा समूह में करीब आठ फीसदी की तेजी रही। एफएमसीजी, धातु, बुनियादी वस्तुएं, यूटिलिटीज और स्वास्थ्य समूहों के सूचकांक भी तीन से छह फीसदी तक चढ़े। संसेक्स में आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के साथ बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की

कंपनियों ने भी बढ़त में योगदान दिया। संसेक्स 2,586.82 अंक की मजबूती के साथ 2,586.82 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। इसका दिवस का निचला स्तर 2,566.36 अंक और निचला स्तर 2,590.22 अंक रहा। अंत में यह गत दिवस की तुलना में 3.62 फीसदी ऊपर 25,862.86 अंक पर बंद हुआ। बीएसई में कुल 2,846.83 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इनमें 9,528 के शेयर तेजी में और 9,091 के गिरावट में रहे जबकि 9,507 कंपनियों के शेयर दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद अंततः अपरिवर्तित रहे। निफ्टी 2,846.65 अंक की तेजी के साथ 1,56,09.05 अंक पर खुला। इसका दिवस का निचला स्तर 1,56,09.05 अंक और उच्चतम स्तर 1,56,09.05 अंक रहा। अंत में यह 3.22 अंक की तेजी के साथ 1,56,09.05 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 50 में से 40 कंपनियों के शेयरों में लिवाली और शेष 10 में बिकवाली का जोर रहा।

## फरवरी में कोर उत्पादन 4.5 प्रतिशत पर

नई दिल्ली। देश की प्रमुख आठ उद्योगों की उत्पादन दर फरवरी 2020 में 4.5 प्रतिशत पर रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आज इस आशय के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में फरवरी तक कुल उत्पादन की दर एक प्रतिशत रही है। कोर उत्पादन के सूचकांक में कोयला, कच्चा तेल, प्रोथिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, सीमेंट, बिजली और इस्पात शामिल होते हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि फरवरी 2020 में कोयले का उत्पादन 90.33 प्रतिशत बढ़ा है। अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक कोयले के उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आलोच्य माह में कच्चे तेल का उत्पादन 6.8 प्रतिशत गिरा है। चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक इसका उत्पादन 6.0 प्रतिशत घटा है।



## जियो अपने उपभोक्ताओं को 10 गुना लाभ देगा: मुकेश

मुंबई। कोरोना वायरस के संकट की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक योगदान में सहयोग कर रहे मुकेश अंबानी ने अब समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो फोन उपभोक्ताओं को 90 गुना लाभ देने का ऐलान किया है। कंपनी ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा कि जियो उपभोक्ताओं को आगामी 90 अप्रैल तक 900 मिनट कॉलिंग और 900 एस एम एस फ्री देगा। इस दौरान वैद्यता खत्म होने के बाद भी इनकमिंग चलता रहेगा। जियो उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन भी ऑनलाइन ही चार्ज करते हैं। जो लोग जियो

# छह सरकारी बैंक इतिहास के पन्नों में हो जायेंगे दर्ज

नई दिल्ली। बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने और वैश्विक स्तर तक बड़े बैंक बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के 90 बैंकों का विलय कर चार बनाने के एक अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही छह सरकारी बैंक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जायेंगे। एक अप्रैल से जो बैंक इतिहास में दर्ज हो जायेंगे उनमें इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड इंडिया बैंक शामिल हैं। इस विलय के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 92 रह जायेगी। बैंकों के विलय को लेकर रिजर्व बैंक भी अधिसूचना जारी कर चुका है। इसके तहत इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में और कॉर्पोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में

एक अप्रैल से विलय हो जायेगा। एक अप्रैल से इलाहाबाद बैंक की शाखाएं इंडियन बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। इसी तरह शाखाएं पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। जबकि सिंडिकेट बैंक की शाखाएं केनरा बैंक की हो जाएंगी। इस तरह से देश में 90 बैंकों का विलय प्रभावी हो जायेगा। विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा बैंक बन जायेगा। भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा आयेगा। केनरा बैंक चौथा बड़ा बैंक होगा जबकि यूनियन बैंक पांचवा बड़ा बैंक बन जायेगा। इलाहाबाद बैंक के विलय से इंडियन बैंक देश का सातवां बड़ा बैंक होगा।

## भाला फेंक एथलीट नीरज ने दान किए 3 लाख रुपये

नई दिल्ली। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और हरियाणा

इस समय कोविड-19 से देश की लड़ाई में मदद करेंगे। "तुर्की से लौटने के बाद नीरज इस समय पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्था में आइसोलेशन में



राज्य राहत कोष में तीन लाख रुपये का दान दिया है। नीरज ने टवीट करते हुए लिखा, "मैंने पीएम राहत कोष में दो लाख और हरियाणा कोविड राहत कोष में एक लाख रुपये का दान दिया है। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी क्षमता अनुसार

अलग रह रहे हैं। नीरज को ओलंपिक में पदक का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कोरोनावायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीरज ने इसे स्थगित किए जाने के फैंसले की सराहना की थी।

# भारतीय पुरुष-महिला हॉकी टीमों 2029 के लिए तैयार

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के टोक्यो ओलंपिक 2029 की नयी तारीखों की घोषणा के बाद भारतीय पुरुष और महिला हॉकी

कारण इन्हे स्थगित कर दिया गया था। हकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने कहा, "ओलंपिक की तारीखों की घोषणा होने से हमें तैयारी और

बता सकते कि टीम किस टूर्नामेंट में खेलेगी। हालांकि पुरुष और महिला दोनों टीमों बेंगलुरु में सुरक्षित हैं और उनके साथ कोच तथा सहायक स्टाफ भी वहां है। हालात सुधरने पर टीमों ट्रेनिंग शुरू करेंगी। भारतीय पुरुष टीम के कोच ग्राहम रीड ने कहा, "ओलंपिक खेलों की नयी तारीख सामने आना बेहतर है। इससे पहले अगले साल होने वाले ओलंपिक की तैयारियां करने में मदद मिलेगी। यह कठिन दौर गुजरने के बाद हमें जल्द ही मैदान पर उतरने की उम्मीद है।" महिला टीम की कोच शुअर्द मरिने ने कहा, "यह अच्छा है कि हमें पता चल गया कि ओलंपिक कब शुरू होंगे और इसको लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। इस वक्त हम सभी एक ही शिविर में हैं और ओलंपिक की नयी तारीखें हमारे लिए अच्छी खबर है। हम मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं और जल्द ही मैदान पर वापसी करना चाहते हैं।"



टीमों का कहना है कि वे ओलंपिक के लिए तैयार हैं और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। आईओसी ने टोक्यो ओलंपिक 2029 की नयी तारीखों की थी। ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस्त 2029 तक होगा। इन खेलों का आयोजन इस वर्ष 28 जुलाई से होना था लेकिन कोरोना वायरस के खतरे के

योजना बनाने में आसानी होगी। हम ओलंपिक के लिए क्वालीफाई पहले से ही कर चुके हैं ऐसे में यह हमारे लिए आसान होगा। हम भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं जिससे पुरुष तथा महिला टीमों का प्रदर्शन बेहतर हो सके।" मुश्ताक अहमद ने कहा, "अभी के हालात में हम इस बारे में नहीं

## कोविड-19 : बीडब्ल्यूएफ ने स्थिर की रैंकिंग

नई दिल्ली। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने मंगलवार को विश्व रैंकिंग स्थिर कर दी है और कहा है कि रैंकिंग 90 मार्च तक जो थी वही रहेगी और इन्हीं के आधार पर कोविड-19 के बाद शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में एंट्री मिलेगी। बीडब्ल्यूएफ ने एक बयान में कहा बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग और जूनियर विश्व रैंकिंग को अगले आदेश तक स्थिर

कर दी है। स्थिरता 92वें सप्ताह तक जारी रैंकिंग की रहेगी जो योनेक्स इंग्लैंड ओपन-2020 के



बाद था। बयान के मुताबिक अगले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में

प्रवेश का आधार 90 मार्च तक जारी रैंकिंग रहेगी। बीडब्ल्यूएफ ने अपने सभी टूर्नामेंट्स 92 अप्रैल तक टाल दिए हैं। बयान में कहा गया है कोविड-19 के कारण, बैडमिंटन समुदाय को मार्च-2020 के मध्य से अप्रैल-2020 के अंत तक अप्रत्याशित निलंबन झेलना पड़ रहा है। इस समय यह बताया मुश्किल है कि अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कब होंगे।

## खिलाड़ियों के वेतन में हो सकती है कटौती : रूत

लंदन। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूत ने कहा है कि उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस के कारण

कर सकता है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण 22 मई तक सभी क्रिकेट गतिविधियां ठप्प पड़ी



उत्पन्न संकट की घड़ी और सत्र पर इसका प्रभाव पड़ने के चलते इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) खिलाड़ियों के वेतन में कटौती

हुई है और ऐसे में बोर्ड को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूत को लगता है कि कोरोना के कारण गतिविधियां ठप्प होने से

केंद्रीय अनुबंध में शामिल खिलाड़ियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। रूत ने कहा, मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में इस पर चर्चा की जाएगी लेकिन यह बातचीत ईसीबी और पीसीए के बीच होगी। हालांकि जब तक इस पर कोई बात नहीं होती मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान सिर्फ खुद को फिट रखने पर केंद्रित है और हम जल्द ही क्रिकेट के मैदान पर वापस लौटना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है और हजारों लोगों की इससे मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण विभिन्न खेल प्रभावित हुए हैं।

## ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वेतन कटौती के लिए तैयार : पेन

मेलबोर्न। अस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने कहा है कि है कि कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट गतिविधियां रुकने



से हुए नुकसान को देखते हुए टीम के खिलाड़ी वेतन कटौती के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में

## कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कुंबले ने दिया योगदान

बेंगलुरु। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री राहत कोष और कर्नाटक राज्य राहत कोष में मंगलवार को दान दिया। कुंबले ने टवीट में कहा कोविड-19 को हराने के लिए हम सभी को एकजुट होकर इससे लड़ना होगा। मैंने पीएम राहत कोष और मुख्यमंत्री (कर्नाटक) राहत कोष में योगदान किया है। कृपया घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। कुंबले ने यह नहीं बताया कि उन्होंने कितनी राशि दान की है। इससे पहले, भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 20 लाख रुपये की राशि दान में दी। रोहित ने प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, जॉमेटो फीडिंग इंडिया और स्ट्रे जॉमेटो की संस्था में दान दिया है। रोहित ने पीएम मोदी और महाराष्ट्र

कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं और इसका उनके घरेलू सत्र पर भी असर पड़ा है। पेन ने कहा कि



उन्हें इस बात की उम्मीद कम है कि टीम बंगलादेश दौरे पर जा पाएगी। उन्होंने साथ ही कहा

कि आईसीसी ने इस बारे में फिलहाल विचार नहीं किया है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को स्थगित किया जाएगा या इसे रद्द किया जाएगा क्योंकि फिलहाल टीमों किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को मंगलवार सुबह पता चला कि उनका बटुआ चोरी हो गया है जिसे वह होबार्ट में अपनी कार में छोड़ आये थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी इस बात से अवगत हैं कि उन्हें अपनी वेतन में कटौती से समझौता करना पड़

सकता है। अस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "इस बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे वेतन में कटौती की जा सकती है। अगर देखा जाए तो फुटबल और अन्य खेलों में भी ऐसा हुआ है और इसे देखते हुए हम इससे अवगत हैं।" पेन ने कहा, "अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी इसमें साथ देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि खिलाड़ियों को कितना वेतन दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी।"

## डेवोन को न्यूजीलैंड से खेलने के लिए मिली हरी झंडी

जोहान्सबर्ग। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में जन्मे डेवोन कोनवे 22 अगस्त से न्यूजीलैंड के लिए खेल सकते हैं। डेवोन इस समय वेल्सिंग्टन से खेलते हैं। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वेल्सिंग्टन से खेलते हुए 90 मैचों में 92.63 की औसत से 9562 रन बनाए हैं। डेवोन ने कहा एक तारीख होना अच्छी बात है। 22 अगस्त याद दिलाती है कि मैं काफी करीब हूँ। यह चयन की गारंटी नहीं देती। मैं इस बात को



जोहान्सबर्ग छोड़ने वाले डेवोन को आईसीसी ने न्यूजीलैंड के लिए खेलने की मंजूरी दे दी है। आईसीसी ने उन्हें 22 अगस्त से पहले टूर मैच और 92 अगस्त से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच शुरू रही सीरीज के लिए सहा हूँ। हमें अपने नेताओं का रक्षा बनने और उनका साथ देने की जरूरत है।

सुनकर खुश हूँ, लेकिन मुझे कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और उम्मीद है कि न्यूजीलैंड टीम के लिए खेला जा काफी अच्छा पल होगा। उन्हें हो सकता है कि अपने पदार्पण के लिए इंतजार करना पड़े क्योंकि इस समय कोरोनावायरस के कारण लिए विशेष मंजूरी भी दे दी है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने



## भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा आइएसआइएस, दिल्ली पुलिस को बना सकता है निशाना

नई दिल्ली। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है तब आइएसआइएसभारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस के उप आयुक्त ने आज कहा कि दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिसकर्मियों को आइएसआइएस अपना निशाना बना सकता है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस

की ओर से कहा गया है कि जो भी जवान दिल्ली में बैरिकेड या फिर जगह-जगह सुरक्षा कारणों से खड़े हैं उन पर आइएसआइएस का निशाना है। इससे पहले भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी दिल्ली पुलिस को सावधान करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने साफ कहा कि

आइएसआइएस अभी बड़ी साजिश रचने में जुटा हुआ है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दो पाकिस्तानी आतंकी जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे और यह आइएसआइएससे संवाद करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि यह दोनों आतंकी कश्मीर से दिल्ली के लिए सड़क मार्ग से निकले थे।

नई दिल्ली। निजामुद्दीन के मरकज में लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और यहां २४ के कोरोना वायरस (कोविड १९)



से संक्रमित पाये जाने के बाद दिल्ली में करीब २० हजार घरों की पहचान कर कड़ाई से होम क्वारंटीन की निगरानी में रखा गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्रियों

### सुशील ने कोरोना

### उन्मूलन कोष में रुपये देने की सहमति दी

पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना वायरस से संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए किए जा रहे उपाय एवं राहत कार्य में सहयोग के



रूप में कोरोना उन्मूलन कोष में तीन करोड़ १८ लाख रुपये देने की आज सहमति दी। मोदी ने कोरोना उन्मूलन कोष में अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना निधि के अवशेष ३.१८ करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। इनमें राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कोरोना उन्मूलन कोष में दी जाने वाली ५० लाख की राशि भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने योजना एवं विकास विभाग के सचिव को इस आशय का पत्र लिख अग्रतर कार्रवाई करने की अपनी सहमति दी है।

तथा उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी। बैजल ने कहा कि मरकज की घटना के बाद २० हजार घरों को चिन्हित कर होम क्वारंटीन किया जायेगा। इसमें सबसे अधिक संख्या दक्षिण पूर्वी दिल्ली की हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन का सभी को कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि भोजन उपलब्ध कराने के लिये ५०० स्थानों को बढ़ाकर ढाई हजार किया जा रहा है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का सख्ती से पालन कराया जा सके। बैजल ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हर स्तर पर जागरूक करने की जरूरत

## फसल कटाई, परिवहन को मगरगा में शामिल करने की मांग

नई दिल्ली। देश भर में कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और अन्य संगठनों ने फसल कटाई और उसके परिवहन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में शामिल करने की मांग की है। इन संगठनों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर कहा है कि देश के गांवों, कस्बों और कई हिस्सों में गेहूँ, धान, मिर्च, दाल आदि खड़ी फसलें कटाई के लिए तैयार हैं लेकिन तालाबंदी और प्रतिबंधों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसकी वजह से फसलों की कटाई, परिवहन और विपणन पर अंकुश लगा हुआ है। हम खेत मजदूरों की मदद के लिए मनरेगा के तहत बेरोजगारी मजदूरी खंड का इस्तेमाल किए जाने की मांग करते हैं। साथ ही खेत मजदूरों

## आंध्र में कोरोना के १७ नये मामले, कुल ४० संक्रमित

विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में पिछले २४ घंटों के दौरान कोरोना वायरस (कोविड १९) के १७ नये मामले आने के साथ ही इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर ४० हो गयी है। यहां आज जारी आधिकारिक वक्तव्य के मुताबिक कुल १४७ लोगों के रक्त नमूनों की जांच में १७ लोग कोरोना से संक्रमित पाये गये। अभी तक ५६१ लोगों की कोरोना संबंधी जांच की जा चुकी है। कोरोना के नये मामलों में से आठ लोगों ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज में एक धार्मिक समारोह में भाग लिया था जबकि छह अन्य दिल्ली के आयोजन में

भाग लेने वाले लोगों के संपर्क में आये थे। इसके अलावा एक अन्य मदीना की यात्रा कर लौटा था जबकि दो अन्य मदीना से लौटने वाले व्यक्ति के करीबी संपर्क में आये थे। राज्य में कोरोना के कुल ४० मामलों में से ११ प्रकासम जिले, नौ गुंटुर, छह विशाखापत्तनम, पांच षणा, चार पूर्वी गोदावरी, दो अनंतपुर तथा एक-एक मामले चित्तूर, नेल्लोर और कुनूल जिले से हैं। कोरोना को लेकर बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की मशीनरी हाई अलर्ट पर है। कल तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या केवल २३ थी।

## मोहल्ला क्लीनिक का एक और डॉक्टर कोरोना पोजिटिव

नई दिल्ली। दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के एक और डॉक्टर को कोरोना वायरस के संक्रमण से ग्रसित पाया गया है। कोरोना

पर ही क्वारंटाइन रहने को कहा है। दिल्ली सरकार ने कहा स्वास्थ्य विभाग की टीम बाबरपुर स्थित मोहल्ला क्लीनिक के इस

आने वाले सभी ८०० लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। १० मार्च को सऊदी अरब से आई एक महिला मौजपुर मोहल्ला क्लीनिक के इस डॉक्टर

के संपर्क में आई थी। सऊदी अरब से लौटी यह महिला दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में रहती है। महिला कोरोना वायरस से ग्रस्त पाई गई है। सऊदी अरब से आई इस महिला के उपचार के दौरान मोहल्ला क्लीनिक का यह डॉक्टर भी संक्रमित हो गया। डॉक्टर के साथ ही उनकी पत्नी और बेटी भी इसका शिकार हो गई हैं। सऊदी अरब से आई महिला के संपर्क में आने से अभी तक ८ लोग कोरोना पोजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए इन लोगों में सऊदी अरब से आई महिला का दिल्ली में रहने वाला भाई और मां भी शामिल हैं। मौजपुर स्थित मोहल्ला क्लीनिक के डॉक्टर की पत्नी और उनकी बेटी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती हैं।



डॉक्टर के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रही है। विशेष समय अवधि के दौरान इस मोहल्ला क्लीनिक में आए सभी रोगियों व अन्य व्यक्तियों को फिलहाल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इससे पहले मौजपुर में कोरोना वायरस की चपेट में आए डॉक्टर के संपर्क में करीब ८०० व्यक्ति आए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी में कहा 'कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए डॉक्टर के संपर्क में

वायरस से ग्रस्त पाया गया यह डॉक्टर उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक का इंचार्ज है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही मौजपुर में मोहल्ला क्लीनिक के एक अन्य डॉक्टर को कोरोना वायरस से ग्रस्त पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने बाबरपुर में मोहल्ला क्लीनिक के बाहर एक नोटिस लगाकर १२ से २० मार्च के बीच क्लीनिक में आए मरीजों से अगले १५ दिनों के तक घर

## शहर से गांव जा रहे १० में से ३ कामगार हो सकते हैं वायरस के वाहक : केंद्र सरकार

नयी दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोई प्रवासी कामगार सड़क पर नहीं है। ऐसी आशंकाएं जाहिर

की ओर) की इजाजत नहीं दिये जा सकने का जिक्र करते हुए प्र

पिठ को बताया, 'इस बात की संभावना है कि शहर से गांव की ओर जा रहे १० में से तीन लोग वायरस के वाहक हों।' उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से एक दिन पहले ही २१ दिन के देशव्यापी

बंद के लागू होने के बाद कामगारों के शहरों से बड़े पैमाने पर पैदल ही अपने मूल निवास स्थान की ओर जाने को रोकने के लिये उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की तरफ से पेश हुए मेहता ने बताया कि कोरोना वायरस से ग्रामीण भारत अब तक प्रभावित नहीं हुआ है और राज्यों को अंतरराज्यीय आवाजाही को पूरी तरह रोकने के लिये परामर्श जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की आवाजाही न हो। यह उनके लिये और गांवों की आबादी के लिये जोखिम भरा होगा। ग्रामीण भारत अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है लेकिन इस बात की आशंका है कि शहर से गांव की ओर जा रहे १० में से तीन लोग वायरस के वाहक हों।

## मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के उलंघन पर प्रशासन ने उठाए सख्त कदम

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का उलंघन करने वालों पर प्रशासन ने सख्त उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र की तरफ से पेश हुए मेहता ने बताया कि कोरोना वायरस से ग्रामीण भारत अब तक प्रभावित नहीं हुआ है और राज्यों को अंतरराज्यीय आवाजाही को पूरी तरह रोकने के लिये परामर्श जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की आवाजाही न हो। यह उनके लिये और गांवों की आबादी के लिये जोखिम भरा होगा। ग्रामीण भारत अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं है लेकिन इस बात की आशंका है कि शहर से गांव की ओर जा रहे १० में से तीन लोग वायरस के वाहक हों।

विवेक जोहरी ने कहा कि पुलिस कमजोर वर्ग के साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। सरकार के निर्देशों का पुलिस सख्ती से पालन कर रही है। पुलिस जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले माल वाहनों को नहीं रोकने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। जनता को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करना चाहिए। वही बाजारों में लगातार बढ़ रही भीड़ और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जहाँ प्रशासनिक कार्यवाही की है। वही प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर में बिट्टन मार्केट, न्यू मार्केट, कोलार और कोटारा

सुल्तानाबाद सहित अन्य स्थानों पर लगने वाले हाट बंद करा दिए हैं। इन हाट बाजारों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों और शहर के लोडिंग रिक्शा संचालकों का समन्वय करके 'आपकी सब्जी-आपके द्वार' योजना शुरू की गई है। भोपाल के जिन क्षेत्रों में कोरोना को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके क्लोज किया गया है। वहां सब्जी के साथ किराने की गाड़ी भी पहुंची गई और जहाँ जरूरतमंद लोगों ने किराना खरीदा। पूरे शहर में सोमवार को २२३ वाहनों से करीब २५ हजार परिवारों तक सब्जी पहुंची। इस दौरान दवा व्यापारियों ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स तो खुले हुए हैं, लेकिन दवाओं की थोक सप्लाई नहीं हो पा रही है। अन्य शहरों से भोपाल आने वाले

और यहां से अन्य शहरों में जाने वाले वाहनों को अनुमति नहीं मिलने से दवाओं की थोक सप्लाई रुक गई है। जबकि पिज्जा, बर्गर और अन्य फूड आइटम की अनलाइन बुकिंग और डिलेवरी भी शुरू हो गई है। पहले दिन ७५० लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। सोमवार को रेस्टोरेंट और किराना मिला कर कुल २८२२ लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। शहर में सब्जी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भोपाल कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने 'आपकी सब्जी-आपके द्वार' योजना तैयार की। रविवार को पहले दिन ६० रुट पर १६४ गाड़ियों से सब्जियों की बिक्री हुई थी। सोमवार को वाहनों की संख्या बढ़ कर २२३ हो गई। मंगलवार को यह संख्या २५० तक पहुंचने गई है। हर एक वाहन को एक रुट दिया गया। नगर निगम के डोर डोर कचरा कलेक्शन वाले वाहनों के लिए तय रुट पर ही सब्जी के वाहन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने लकडाउन की स्थिति में जिलों में जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं सब्जी, फल, अंडे समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से छोटे पार्सलों के लिए पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश का उल्लेख करते हुए संभाग के सभी कलेक्टरों को तत्काल अपने-अपने जिलों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चौन बनाए रखने के लिए रेलवे से समन्वय स्थापित कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।



की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवासी कामगारों के पलायन से कोविड-१९ का व्यापक प्रसार हो सकता है। सलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसे पलायन (शहरों से गांव

की ओर) की इजाजत नहीं दिये जा सकने का जिक्र करते हुए प्र

## बाहर फंसे राज्य के नागरिकों की मदद करने के लिये बिहार सरकार प्रतिबद्ध : नीतीश

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाहर फंसे बिहार के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये मंगलवार को एक समीक्षा बैठक की और लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी सहायता करने के लिये प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक विज्ञापित में बताया गया कि नीतीश ने विदेश या देश के अन्य हिस्सों से बिहार आए लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। पटना के एक अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिहार में बाहर से अब तक १ लाख ८० हजार ६५२ लोग आए

हैं। उनकी स्क्रीनिंग करायी जा रही है। 'गरुड़ एप' के माध्यम से उन पर सघन निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपदा सीमा राहत केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही गांवों के स्कूलों में भी आए हुए प्रवासियों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आवास के दूरभाष, स्थानिक आयुक्त के हेल्पलाइन नंबर तथा आपदा प्रबंधन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर फंसे हुए लोगों से प्राप्त सूचनाओं के आार पर उनकी समस्याओं को एवं उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली गई है। उनके फीडबैक के आधार पर उन लोगों की परेशानियों को दूर किया जा रहा है। बैठक

के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग बाहर से बिहार आए हैं उनकी स्क्रीनिंग कराई जाए और उनके, भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था के साथ-साथ उन्हें चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाए। नीतीश ने राज्य के सीमावर्ती जिलों में आपदा सीमा राहत केंद्रों में पूरी व्यवस्था करने, गांव के स्कूलों में लोगों के आवासन एवं भोजन की उचित व्यवस्था करने और उन केंद्रों पर सरकारी कर्मचारी को प्रभारी बनाकर बेहतर ढंग से काम कराने को कहा। उन्होंने मुखिया, सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी समुचित प्रबंध करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पटना जैसे शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जो राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी

संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग बिहार के बाहर अन्य राज्यों में लकडाउन के कारण फंसे हुये हैं, वे जहां हैं वहीं पर रहें। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार उनकी पूरी मदद करने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अन्य राज्यों की सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुये सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। नीतीश ने बाहर रह रहे लोगों के फीडबैक के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लकडाउन के मद्देनजर सरकार ने सभी राशन कार्डधारियों को १००० रुपए देने का जो निर्णय लिया था। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस राशि को जल्द से जल्द लाभुकों के खाते में अंतरित

किया जाए। उन्होंने कहा कि लोग जहां भी हैं सामाजिक दूरी और लकडाउन का पालन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय, गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, परिवहन

विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल एवं खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव पंकज कुमार पाल सहित अन्य अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद अब राज्य में इसके मरीजों की संख्या २१ हो गई है। कतर से लोटे मुंगेर निवासी एक व्यक्ति की गत २१ मार्च को पटना एम्स में मौत हो गयी थी। इस बीच, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना' कोष से राज्य में बनाए गए कोरोना वायरस उन्मूलन कोष में ३.१८ करोड़ रुपये का योगदान दिया। 'मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना' विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का परिवर्तित रूप है।



